भारत के समग्र और तीव्र विकास हेतु
भारतीय जनता पार्टी का

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दृष्टिकोण

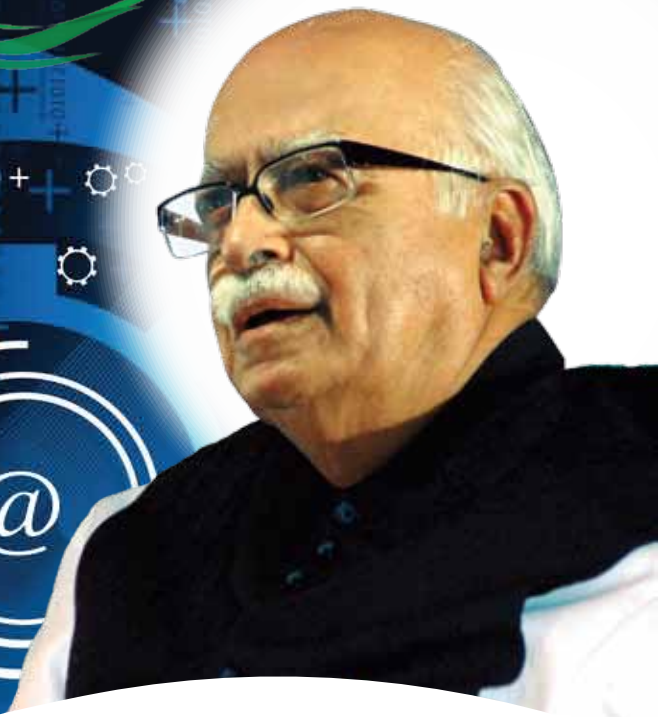

Advani *for* PM

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.) दृष्टिकोण की मुख्य बातें

@ तीन वर्षों में नागरिक पहचान संख्या (CIN) के साथ बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र; दूसरी सभी पहचान प्रणालियों को इसमें समाहित किया जाएगा।

@ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित १.२ करोड़ नये रोजगार।

@ जल संरक्षण, भूमि संवर्धन, अधिप्राप्ति, विपणन और किसान की ऋण आवश्यकताओं, अपशिष्ट निपटान के लिए आई. टी. का इस्तेमाल करते हुए तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) को ''प्रयोगशाला से लेकर जमीन तक'' पहुंचाकर कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाना। इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

@ सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.) का सभी दुकानों, छोटे तथा मझोले उद्योगों और गैर-औपचारिक क्षेत्र के लिए लाभ उठाना।

@ एक करोड़ विद्यार्थियों को १०,००० रुपये के मूल्य पर लैपटाप कम्प्यूटर मिलेंगे। जो विद्यार्थी कम्प्यूटर खरीद नहीं सकते हैं उन्हें ब्याज रहित ऋण दिये जायेंगे।

@ सभी स्कूलों और कालेजों में इन्टरनेट पर आधारित शिक्षा दी जाएगी।

@ भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय मिशन।

@ प्रत्येक कस्बे और गांव में केबल टीवी की कीमत पर अपलोड और डाउनलोड डाटा ट्रांसफर की अनलिमिटेड सीमाओं के साथ ब्रॉडबैंड इन्टरनेट सेवा।

@ पांच वर्षों में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या ४० करोड़ से बढ़ाकर १०० करोड़ की जाएगी। मोबाइल उपभोक्ताओं के बराबर इन्टरनेट उपभोक्ता। हरेक बीपीएल परिवार को मुफ्त में स्मार्ट मोबाइल फोन दिया जाएगा।

@ सभी भारतीय नागरिकों को ई-बैंकिग की सुविधाओं के साथ बैंक खाते के माध्यम से शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन। कल्याण निधियो का उनके खाते में सीधे हस्तांतरण। हमारा वादा : ***हर हिन्दुस्तानी का बैंक खाता; हर बीपीएल परिवार का स्मार्ट मोबाइल फोन। हर गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा; हर स्कूल में इंटरनेट शिक्षा। सबको रोजगार; शासन जनता के द्वार।***

@ आई. टी. प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक नागरिक के लिए एक बुनियादी स्वास्थ्य बीमा योजना। अस्पताल में नगदी बगैर भर्ती।

@ सभी जनस्वास्थ्य केन्द्रों को एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

@ केन्द्र से लेकर पंचायतों तक प्रत्येक सरकारी कार्यालय को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना। गुजरात की ''ई-ग्राम विश्व ग्राम'' योजना को देश भर में कार्यान्वित किया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.) दृष्टिकोण की मुख्य बातें

@ भारत को पांच वर्षों में आई. टी कसौटियों के प्रत्येक क्षेत्र में चीन के बराबर लाना।

@ मीडिया कन्वरसन : राष्ट्रीय डिजिटल राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री डिजिटल ग्राम सड़क योजना से अगली पीढ़ी का नेटवर्क आधारभूत ढांचा तैयार करना जो डाटा, वॉयस और हाई-डेफिनिशन वीडियो जैसे मीडिया को समरूप करेगा।

@ अबाधित वीओआईपी (VOIP) शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

@ डाकघरों को आई.टी. पर आधारित बहु-सेवा केन्द्रों में बदला जाएगा। टेलीफोन बूथों को इन्टरनेट क्योस्क में बदला जाएगा।

@ नागरिकों के लिए १-८०० बीएसएनएल का एक साधारण टोल-फ्री नम्बर उपलब्ध रहेगा जो २४ घंटे x सातों दिन x वर्ष के ३६५ दिन खुला रहेगा जिस पर वे अपने सांसदों से सम्पर्क कर सकते हैं।

@ भारत सरकार ''ओपन स्टैंडर्ड'' और ''ओपन सोर्स'' साफ्टवेयर का मानकीकरण करेगी। भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) से इतर सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के मानक-निर्धारण निकाय की स्थापना की जाएगी।

@ वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा इस्तेमाल हेतु सस्ती और सभी जगह उपलब्ध करायी जाएगी।

@ भूमि तथा संपत्ति के रिकार्डों को डिजिटल बनाया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाएगा।

@ साइबर युद्ध, साइबर पर आतंकवाद के हमले से मुकाबला, और राष्ट्रीय डिजिटल परिसंपत्तियों की साइबर सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र निकाय-डिजिटल सुरक्षा एजेंसी की स्थापना की जाएगी।

@ आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू आई.टी. हार्डवेयर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जायगा।

@ अतंर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ प्रभारों को कम करने हेतु डोमेस्टिक हॉस्टिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा।

@ महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा समाज के दूसरे कमजोर वर्गों को आई.टी. पर आधारित विकास के दायरे में लाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

@ भारत की मूल्यवान सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर के संरक्षण हेतु आई.टी. का इस्तेमाल।

समग्र विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) : भारतीय जनता पार्टी का समृद्ध भारत, सशक्त भारत बनाने का वादा

प्रिय मित्र,

मुझे १५वीं लोकसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) दृष्टिकोण को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सूचना और प्रौद्योगिकी द्वारा शुरू की गई क्रांति ने भारत को सामाजिक-आर्थिक विकास की अनेक भयंकर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। भारत की जनसंख्या के आकार विशेषकर शिक्षित युवाओं की वर्तमान और भावी जनसंख्या को देखते हुए यह अवसर और भी महत्वपूर्ण है। भारत के युवा इसका सबसे बड़ा संसाधन हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत को एक सुदृढ़ और सम्पन्न राष्ट्र बनाने हेतु इस संसाधन को समृद्ध तथा शक्ति-सम्पन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले दस वर्षों में भारत की प्रगति और खुशहाली का श्रेय बहुत कुछ सूचना प्रौद्योगिकी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे महत्वाकांक्षी उद्यमियों तथा आई.टी. क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यावसायिकों (प्रोफेशनल्स) की उपलब्धियों की हृदय से सराहना करती है। तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और आई.टी. पर आधारित विकास में अब तक भारत की उपलब्धियों, संभावनाओं और आवश्यकताओं का एक अंशमात्र है। हमें अभी और अधिक उपलब्धियां हासिल करनी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकार (१९९८-२००४) की प्रमुख पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास में अपने योगदान पर गर्व है। एन.डी.ए. सरकार ने अपनी दूरदर्शी नई दूरसंचार नीति के साथ दूरसंचार क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की नींव रखी। इससे न केवल सॉफ्टवेयर और आई.टी. पर आधारित सेवा उद्योग में प्रगति हुई बल्कि भारत को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मार्केट बनाने में भी मदद मिली। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) कार्यदल ने भारत के साफ्टवेयर उद्योग को एक वैश्विक अगुवा के रूप में उभरने में मदद की। पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी के एक अलग मंत्रालय की स्थापना की गई।

सन् २००६ के लोकसभा चुनावों में जनता से जनादेश हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक नागरिक के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने हेतु आई.टी. का इस्तेमाल करके भारत की प्रगति के लिए और भी अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। भारतीय जनता पार्टी का ३६०-डिग्री दृष्टिकोण भारत के लिए आई.टी. पर आधारित एक नया आर्थिक मॉडल पेश करेगा जो भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता, बड़ी संख्या में विविध उद्योगों और आर्थिक रूप से श्रेणीकृत बाजारों जिनकी ओर अर्थव्यवस्था का स्थानीकरण करने हेतु अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है, के लिए अधिक प्रासंगिक है। जबकि हमारा अधिकांश सॉफ्टवेयर उद्योग विदेशी अर्थव्यवस्थाओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए मेहनत करता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार एक ऐसा नया नीति वातावरण तैयार करेगी जिसमें हम मुख्यतः भारत - मैं यह कहूंगा, भारत के सतत् विकास - के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलोजी) का इस्तेमाल कर सकें। विशेषकर, इसका तात्पर्य यह होगा कि इससे कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा विकास, छोटे तथा मझोले उद्यमों, अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र, सभी के लिए सस्ती दरों पर स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं, सभी के लिए उपयोगी शिक्षा, पारदर्शी शासन, प्रत्येक क्षेत्र में उन्नत उत्पादकता, ऊर्जा किफायत और सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा, बेहतर न्याय वितरण और अंततः आंतरिक एवं बाह्य राष्ट्रीय सुरक्षा को जबरदस्त बल मिलेगा। हमारा लक्ष्य भारत के प्रत्येक क्षेत्र और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बेहतर जीवन-स्तर मुहैया कराना है।

भारतीय जनता पार्टी के आई.टी. दृष्टिकोण से (क) वर्तमान आर्थिक संकट से निपटने (ख) बड़े पैमाने पर उत्पादक स्वरूप के रोजगार अवसर सृजित करने (ग) उन्नत और विस्तारित शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के जरिए मानव विकास में तेजी लाने (घ) भ्रष्टाचार को रोकने और (ड.) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

इसके लिए, हमारे देश के प्रत्येक कोने में पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ अगली पीढ़ी का नेटवर्क आधारभूत ढांचा होगा। इंटरनेट को बिजली की तरह सर्वव्यापक बनाया जाएगा। इससे, आर्थिक और भौगोलिक असमानताएं दूर हो जाएंगी और प्रत्येक नागरिक को बराबर के अवसर प्राप्त होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का नया आधारभूत ढांचा घरों को सशक्त बनाएगा और भारत को एक समतावादी, सद्भावपूर्ण तथा खुशहाल राष्ट्र में परिवर्तित करने हेतु लोगों को प्रबुद्ध करेगा। यही भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है जो २१वीं सदी को भारत की सदी बनाने के हमारे व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।

> "यदि चीन ने भौतिक आधारभूत ढांचे में विश्व को मात दी है तो भारत विश्व को सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के आधारभूत ढांचे में शिकस्त दे सकता है"

भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन आगामी चुनाव में भारत की जनता का समर्थन चाहते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की भावी सरकार उत्साह, महत्वाकांक्षा और दृढ़-संकल्प के साथ तेजी से इस आई.टी. दृष्टिकोण को कार्यान्वित करेगी जिसे हमारे युवा आई.टी. प्रोफेशनल्स ने हाल के वर्षों में उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है।

आपका

पृष्ठभूमि

- **वाजपेयी सरकार का गौरवशाली रिकॉर्ड**
  - राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एन. डी.ए.) सरकार ने अपनी दूरदर्शी नई दूरसंचार नीति के साथ दूरसंचार क्षेत्र में जबरदस्त विकास की नींव रखी
  - सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) विभाग की स्थापना
  - भारत को सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रधानमंत्री के कार्यदल का गठन
- **आगे की ओर बढ़ते हुए**
  - भारतीय जनता पार्टी अगले पांच वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) की मदद से भारत की बहुमुखी प्रगति के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
  - सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) विभाग की स्थापना
  - हमारे तीन लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं : सुशासन, विकास और सुरक्षा को हासिल करने के लिए हमारे मार्गदर्शन हेतु दृष्टिकोण

इस दृष्टिकोण का प्रभाव

- वर्तमान आर्थिक संकट से निपटना
- बड़े पैमाने पर उत्पादक स्वरूप के रोजगार अवसर सृजित करना
- अत्यधिक उन्नत और विस्तारित शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के जरिए मानव विकास को गति प्रदान करना
- भ्रष्टाचार को रोकना
- भारत की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना
- भारत के आई.टी. उद्योग (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर) को घरेलू (विशेषकर ग्रामीण) अर्थव्यवस्था में एक नया विकास क्षेत्र उपलब्ध कराना
- शहरों की ओर पलायन को नियंत्रित करना

कनेक्टिविटी क्रांति: अधूरे कार्य को आगे बढ़ाना

महत्वाकांक्षा सफलता की जननी है। भारत के एक लोकप्रिय भूतपूर्व राष्ट्रपति ने टिप्पणी की थी कि भारतीय परिस्थितियों में छोटा लक्ष्य रखना अपराध है।

जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह घोषणा करते हुए २ जनवरी, २००० को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) का उद्घाटन किया था कि भारत में ५ वर्षों के दौरान विश्व श्रेणी के राजमार्गों का जाल बिछ जाएगा तब अनेक नकारने वाले लोग भी थे जिन्होंने यह कहा था कि ऐसी महत्वाकांक्षा भारत के लिए अनुचित है। लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ने उन्हें गलत साबित कर दिया। स्वतंत्रता के प्रथम ५० वर्षों में भारत में प्रतिवर्ष ११ किलोमीटर की दर से ४/६ लेन वाले केवल ५५६ कि.मी. राजमार्ग ही बनाये गए थे। जब मई, २००४ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ने सत्ता छोड़ी तब ११ किलोमीटर प्रति दिन के निर्माण दर से ४/६ लेन वाले २५,००० कि.मी. राजमार्ग निर्माणाधीन थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनवरी २००१ में इंफोसिस कैम्पस में

इसी प्रकार, जब श्री वाजपेयी ने सन् २००० में अपने जन्मदिन (२५ दिसम्बर) पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी उस समय भी अनेक लोगों ने भारत के प्रत्येक गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ने के उनके वादे पर आशंका व्यक्त की थी। बहरहाल, कुल ६,००,००० गांवों में से लगभग १,८६,००० गांव स्वतंत्रता-प्राप्ति के पांच दशकों से भी अधिक अवधि के बाद अभी भी सड़कों से वंचित है। श्री वाजपेयी ने एक बार कहा था, ''इन राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण करके हम भारत के नक्शे पर केवल कोई नई रेखाएं नहीं खींच रहे हैं बल्कि भारत और इसकी जनता की भाग्य रेखा को पुनः लिख रहे हैं।''

''सैंकड़ों बंगलौर फले-फूलें''

यह आह्वान पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नवम्बर 1998 में बंगलौर में सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क का उद्घाटन करते हुए किया था। निश्चित रूप से पिछले दशक में अनेक भारतीय ाहरों - पुणे से पटना, कोयम्बटूर से चण्डीगढ़; और गांधीनगर से गुवाहाटी तक - ने आई.टी. व्यवसाय में वृद्धि दर्ज की है।

''कनेक्टिविटी क्रांति'' जैसाकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण में उल्लेख किया गया है, में २०२० तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस दृष्टिकोण में भौतिक कनेक्टिविटी भारत की सड़कों, रेल नेटवर्क, आंतरिक जलमार्गों और बंदरगाहों, हवाई अड्डों और नागरिक उड्डयन के आधारभूत ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण शामिल था। डिजिटल कनेक्टिविटी में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत ढांचे तथा सेवाओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इसी तरह की एक महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया था। इसके अलावा, सरकार ने नदी कनेक्टिविटी के लिए भी एक योजना तैयार की थी।

दुर्भाग्यवश, यूपीए के ५ वर्ष का शासनकाल इस कनेक्टिविटी क्रांति को साकार करने में समय को बर्बाद करने वाला सिद्ध हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी वर्ष २००९ के चुनावों में जनता का जनादेश प्राप्त करती है तो यह न केवल वाजपेयी सरकार द्वारा निर्धारित अधूरे कार्यों को ही पूरा करेगी बल्कि सड़कों के साथ-साथ समग्र विकास करने हेतु भारत को और आगे भी ले जाएगी।

बुनियादी बदलाव (Paradigm Shifting Movements)

1960 का दशक	1970 का दशक	2009 का दशक
खाद्यान्न की कमी	पोषाहार की कमी	विकास की कमी
हरित क्रांति	श्वेत क्रांति	डिजिटल क्रांति

डिजीटल क्रांति क्या है

गरीबी निवारण, कृषि और ग्रामीण विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी सेवाओं, वित्तीय सेवाओं,न्याय वितरण और सुरक्षा के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का इस्तेमाल करके शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक ढांचा

देश में बदलाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) भारत के विकास परिदृश्य को कैसे बदलेगी

वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट इस बात का साफ संकेत है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। विश्व की अर्थव्यवस्था में पश्चिम का आधिपत्य कुछ ही समय में बीते दिनों की बात हो जायेगा। वर्तमान संकट ने भारत के लिए नये अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा किए हैं। हम चुनौतियों से कैसे निपटे और कैसे उन्हें अवसरों में बदलें? इसका उत्तर हम फरवरी २००९ में हुई फिक्की की ८१वीं वार्षिक आम सभा में श्री लालकृष्ण आडवाणी के भाषण में पाते हैं : ''जिस प्रकार विश्व की अर्थव्यवस्था का गुरुत्व केन्द्र पश्चिम से एशिया में स्थानांतरित हो गया है, उसी तरह हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का गुरुत्व केन्द्र ''इंडिया'' से ''भारत'' – कृषि, हमारे गांवों, छोटे तथा मझौले उद्यमों और अर्थव्यवस्था के असंगठित तथा गैर-औपचारिक क्षेत्रों में परिवर्तित होना चाहिए।''

'भारत' से तात्पर्य सिर्फ ग्रामीण जनसंख्या से नहीं है बल्कि शहरी गरीब और मध्यम वर्गों से भी है। ये लोग कांग्रेस सरकारों के विकास मॉडल में शामिल होने से वंचित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद भारत पर लम्बे समय तक शासन किया है जिसने न सिर्फ शहरों में अमीर और गरीब के बीच खाई पैदा की है बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी इतनी बड़ी खाई उसी की देन है।

भाजपा का विश्वास है कि सूचना प्रौद्योगिकी भारत के विकास के केन्द्र को भारत को संतुलित क्षेत्रीय और सामाजिक विकास की ओर तेजी से ले जाने हेतु अधिक कारगर साधन उपलब्ध कराती है।यह मूलभूत भौतिक अवसंरचना और सेवाओं जैसे-ऊर्जा, पानी, सड़क, रेलवे, शहरी और ग्रामीण सुविधाओं आदि का विकल्प नहीं हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी न सिर्फ भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और क्षमता बढ़ाने का काम करती है बल्कि सभी नागरिकों को सशक्त बनाने के नये साधन भी मुहैया कराती है। अब तक सूचना प्रौद्योगिकी का जबरदस्त लाभ ''इण्डिया'' में ही दिख रहा है, अधिकांश ''भारत'' अभी इससे अछूता है। भाजपा इस डिजिटल खाई को पाटेगी।

गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई 'ई-ग्राम विश्व ग्राम' योजना इसका अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार की योजना को पूरे देश के गांवों में लागू करने के लिए भाजपा की भावी सरकार कटिबद्ध है जिसमें ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हर सुविधाएं मौजूद होंगी। यह ग्रामीण जनसंख्या को काफी सशक्त बनाने में प्रभावी होगी। यह योजना पूर्व राष्ट्रपति डा० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की अवधारणा पुरा (PURA) (Provision of Urban Amenities in Rural Areas) को पूरा करने में योगदान देगी।

यद्यपि १९६० के दशक की हरित क्रांति और १९७० के दशक की श्वेत क्रांति उपयोगी रही हैं लेकिन उनके दायरे सीमित थे। इसके विपरीत, भाजपा का डिजिटल क्रांति दृष्टिकोण व्यापक है। यह आर्थिक और सामाजिक विकास के सभी पहलुओं – निर्माण, कृषि, शिक्षा, टेलीमेडीसिन, ई-जस्टिस, ई-सिक्योरिटी, महिलाओं के स्व-सहायता समूह (सेल्फ हेल्पग्रुप) से लेकर ऊर्जा की बचत वाले, बस रूट, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा से लेकर सुशासन के जरिए लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करें। यह डिजिटल क्रांति संभव है। सूचना प्रौद्योगिकी वास्तव में भारत का कायाकल्प कर सकती है और भारत को सशक्त बना सकती है।

> ''भारत की शानदार उपलब्धियों में अभी तक आई. टी. क्षेत्र के हमारी प्रतिभाशाली युवाओं के एक छोटे से वर्ग को जो अच्छी शिक्षा प्राप्त है, ने अर्जित की है। कल्पना कीजिए जब प्रत्येक युवा भारतीय की गुणवत्तावाली शिक्षा और विश्वस्तर के आई.टी. आधारभूत ढांचे तक पहुंच होगी, तो भारत क्या हासिल कर सकता है।''
>
> –लालकृष्ण आडवाणी

भारत के लिए हमारा वादा

अकेले सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के क्षेत्र में
1.2 करोड़ नई ग्रामीण नौकरियां

प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कम से कम एक नया गैर–कृषि रोजगार उपलब्ध कराने के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति की ओर

प्रत्येक गांव में औसतन 20 आई.टी. आधारित रोजगार

6 लाख गांव X 20 आई.टी. से सम्बन्धित नौकरियां = 1.2 करोड नौकरियां
1.2 करोड कमाऊ सदस्य + प्रत्येक पर 4 निर्भर सदस्य =

6 करोड़

ग्रामीण भारतीय लाभान्वित

डिजिटल क्रांति

रोजगार

रोजगार, और रोजगार, और अधिक रोजगार...

भाजपा मानती है कि भारत के सम्मुख सर्वाधिक बड़ी चुनौती है अपनी विशाल और लगातार बढ़ती युवा जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार आर्थिक उदारीकरण के बाद से बेरोजगारी दर बढ़ रही है और कृषि श्रमिकों में यह दर और ज्यादा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (२००७-२०१२) का दस्तावेज बताता है कि एनडीए सरकार के समय रोजगार के अवसर इसके पूर्व की सरकार की तुलना में ज्यादा उपलब्ध हुए। ''१९९९-२००० से २००४-२००५ के बीच लगभग ४.७ करोड़ कार्य अवसर सृजित हुए जबकि तुलना में १९९३-९४ से १९९९-२००० की अवधि में सिर्फ २.४ करोड़ अवसर ही सृजित हुए।'' यूपीए के शासन में न केवल नए रोजगार की वृद्धि दर नीचे चली गई अपितु विद्यमान रोजगार भी खतरे में पड़ गए हैं।

पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख प्रवृत्ति उभरी है- कार्यबल का 'अनौपचारिकरण' (Informalisation) । अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र अब कार्यबल का ९३ प्रतिशत है। दुर्भाग्य से इसे शिक्षा या कौशल सुधारने के किसी संस्थागत तंत्र का समर्थन न होने से परिणामतया इसकी आय तथा श्रम उत्पादकता नीचे है। ग्यारहवीं योजना दस्तावेज दर्ज करते हैं : '४६ करोड़ श्रमिकों में से ९.४ करोड़ इतना कम कमाते हैं कि वे गरीबी रेखा से नीचे है। यदि यह अधिकांशतः रोजगार में लगे श्रमिक हैं तो अनेकानेक गरीब जो बेरोजगार हैं, अवश्य ही ज्यादा शोचनीय स्थिति में है।'' साफ है कि भारत गरीबी उन्मूलन, पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने या अच्छे पढ़े लिखे और प्रशिक्षित मानव बल के मामले में परम्परागत रणनीतियों पर भरोसा नहीं कर सकता।

भाजपा मानती है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के सामाजिक उपकरण के रुप में उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। आईटी के माध्यम से प्रत्येक गांव में कम से कम २० नए रोजगार और स्व रोजगार के अवसरों को सृजित किया जा सकता है।

- कृषि, मूल्यवर्धित कृषि व्यापार, पशुपालन, भूमि और जल प्रबधन;
- ग्रामीण बाजार, समीपवर्ती शहरों और कस्बों, बैंकिंग और सूक्ष्म-वित्तीय सेवाओं से बाजारों का सम्पर्क;
- ग्रामीण कला, हस्तषिल्प और उद्योगों का आधुनिकीकरण;
- इंटरनेट पर आधारित शिक्षा और ग्रामीण कार्यबल का कौशल विकास;
- टेलीमेडिसिन्स; सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित पशुपालन सेवाएं;
- पंचायत आधारित ई-गर्वनेंस पहलें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना और अन्य सरकारी योजनाओं की सामुदायिक निगरानी;
- विद्युत, पेयजल और अन्य सुविधाओं का कुशल प्रबन्धन;
- स्थानीय समुदाय पर आधारित सूचना-मनोरंजन;
- कॉमन सर्विस सेंटर (ऑनलाइन बिलों का भुगतान, नागरिक सम्बन्धी सूचनाओं इत्यादि तक पहुंच);
- इन सभी विभिन्न कामों के लिए स्थानीय भाषाओं में ग्रामीण सामाग्री का सृजन;
- बाहरी अर्थव्यवस्था की जरुरतों की सेवा के लिए, सार्वभौमिक पहुंच वाले ब्राडबैंड इंटरनेट समर्थित ग्रामीण बीपीओ;

भारत में लगभग ६ लाख गांव हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आई.टी. पर आधारित कम से कम १.२ करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। यदि यह सम्भव है तो इसे यथार्थ में बदलना चाहिए। भाजपा के पास यह दृष्टि है और वह इसे साकार भी करेगी।

भाजपा का वादा : सभी का IT से नाता

हर हिन्दुस्तानी का बैंक खाता
हर BPL परिवार को स्मार्ट फोन
हर गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा
हर स्कूल में इंटरनेट शिक्षा
सबको रोजगार; शासन जनता के द्वार

क्वरेज

- इंटरनेट आधार
- 10K लेपटॉप
- हार्डविंग इंडस्ट्री
- हार्डवेयर इंडस्ट्री
- ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड, सॉफ्टवेयर

बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र

- डिजीटल क्रांति का केन्द्र-बिन्दु बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र होगा।
- बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में शुरू किया था; जिसकी वर्तमान यू.पी.ए. सरकार द्वारा उपेक्षा की गई
- यह कार्य तीन वर्षों में पूरा किया जाना है।
- हम सभी पहचान-पत्रों (चुनाव पहचान-पत्र, आयकर पैनकार्ड (PAN), राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) को मिलाकर एक साझा पहचान-पत्र : नागरिक पहचान संख्या (CIN) बनायेंगे।
- बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र के माध्यम से सभी लाभ।

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एमएनआईसी) हमारी डिजिटल नीति का केन्द्र-बिन्दु

भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) दृष्टिकोण के कार्यान्वयन का केन्द्रबिन्दु बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एमएनआईसी) है। जैसाकि नाम से साफ है कि बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एमएनआईसी) एक ऐसा अकेला दस्तावेज होगा जिसे बी.पी.एल. कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने या कॉलेज में प्रवेश लेने हेतु भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

एम.एन.आई.सी. कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल (१९९८-२००४) में शुरू किया गया था। लेकिन यूपीए सरकार ने इस परियोजना का गला घोंट दिया और पांच वर्षों के बाद भी इसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यहां तक कि परियोजना की वेबसाइट (http://mnic.nic.in) 'निर्माणाधीन' दिखाई गई है। जनवरी २००९ में ही यूपीए सरकार ने इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाने का एक सांकेतिक प्रयास किया जब इसने योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में एक Unique Identification Authority of India (भारतीय एकमात्र पहचान प्राधिकरण) की स्थापना की। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठगन्धन की सरकार आई तो हम यूपीए सरकार की इस लापरवाही और आधे-अधूरे प्रयासों की तुलना में इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हम नागरिक अधिनियम १९५५ में संशोधन करेंगे ताकि भारतीय नागरिकता विनियामक प्राधिकरण (सी.आर.ए.आई.) की स्थापना करने हेतु भारत के जनगणना महापंजीयक (Registrar General of the Census of India) और भारतीय एकमात्र पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) के कार्यालय को मिला देंगे। भारतीय नागरिकता विनियामक प्राधिकरण की नागरिकों के एक राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एन.आर.सी) का रखरखाव करने और इसे बिल्कुल अद्यतन बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी।

यूपीए सरकार की उदासीनता का प्रमाण : MNIC वेबसाइट अभी भी निर्माणाधीन!

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के आधार पर भारतीय नागरिकता विनियामक प्राधिकरण (सी.आर.ए.आई.) प्रत्येक नागरिक को एक एकमात्र नागरिकता पहचान संख्या (सी.आई.एन.) के साथ प्रत्येक नागरिक को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम.एन.आई.सी.) जारी करेगा। भारतीय नागरिकता विनियामक प्राधिकरण (सी.आर.ए.आई.) २४ घण्टे सातों दिन ऑनलाइन उपस्थिति का रखरखाव करेगी और सरकार, कानून प्रवर्तन और प्राधिकृत संस्थाओं को समर्थ बनाएगी जिससे उनके कम्प्यूटर सिस्टम वास्तविक समय पर बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम.एन.आई.सी.) के डाटाबेस की 'देखभाल' कर सकें। संशोधित नागरिकता अधिनियम इसे सभी नागरिकों के लिए कानून के तहत आवश्यक बनाएगा कि वे बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करें। नए जन्मे बच्चे के माता-पिताओं को अपने बच्चे के जन्म लेने के तत्काल बाद बच्चे के लिए एक एम.एन.आई.सी. हेतु आवेदन करना पड़ेगा।

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम.एन.आई.सी.) से बहुविध लाभों की अपेक्षा की गई है जैसे :

१. साधारण नागरिकों द्वारा अनेक पहचान दस्तावेजों को साथ लेकर चलने की जरूरत को समाप्त करना।
२. संस्थाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा तत्काल जांच करने और किसी भी व्यक्ति की पहचान को वैद्य ठहराने की योग्यता।
३. कर संग्रहण और कल्याण योजनाओं के संवितरण पर नजर रखना।

भारतीय जनता पार्टी बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम.एन.आई.सी.) के कार्य को ३ वर्ष की कार्यावधि में पूरा करने का वादा करती है।

डिजीटल राजमार्ग

डिजिटल
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

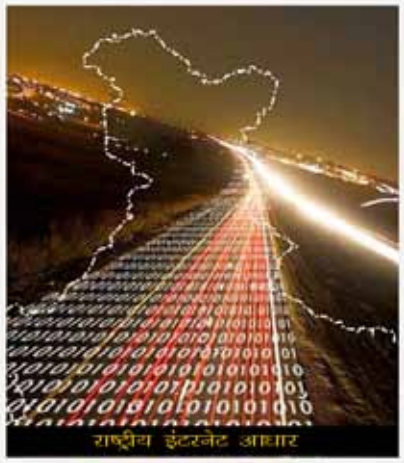

डिजिटल
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

डिजीटल राजमार्ग

- केबल टीवी की कीमत (लगभग २०० रूपये प्रतिमाह) पर असीमित ब्राडबैंड इंटरनेट सेवा (२ एमबीपीएस अपलोड एंड डाउनलोड)
  - मूल्य संवर्धित सेवा (वीएएस) के माध्यम से राजस्व
- पांच वर्षों में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या ४० करोड़ से बढ़ाकर १०० करोड़ की जाएगी।
  - ३जी का कार्यान्वयन
- इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाकर मोबाइल उपभोक्ताओं के बराबर करने का लक्ष्य
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिग की सुविधा सभी लोगों की पहुंच में लाने और कम लागत पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य
- इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी (VoIP) बे-रोकटोक उपलब्ध करायी जाएगी।

डिजिटल राजमार्ग

बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) और अन्य कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश में कम्प्यूटिंग और नेटवर्क का आधारभूत ढांचा सही ढंग से काम करे। इसके लिए दो बातें जरूरी हैं : एक राष्ट्रीय इंटरनेट आधार और सर्वाधिक सुदूर तथा बिखरी जनसंख्या वाले गांवों तक कनेक्टिविटी।

भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार एक त्रुटिरहित, प्रचुर क्षमता वाला राष्ट्रीय इंटरनेट आधार ढांचा तैयार करेगी। इसके साथ ही, कोई गांव जो व्यावसायिक आईएसपी (इंटरनेट सर्विस प्रोवाइटर) की परिधि में न आता हो, को सरकार द्वारा समर्थित योजना के तहत इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

ब्रॉडबैंड की पुनर्परिभाषा

भाजपा चाहती है कि भारत के लोग इंटरनेट के लाभ प्राप्त करें और समृद्ध विजुअल इन्फोरमेशन तक उनकी पहुंच बने जोकि अच्छे ब्रॉडबैंड कनेक्षन के माध्यम से संभव है।

दुःखद यह है कि भारत में 'ब्रॉडबैंड' अपनी सभी प्रासंगिकता खो चुका है। अनेक लोगों के लिए अभी भी 'वर्ल्ड वाइड वेब', 'वर्ल्ड वाइट वेट' बना हुआ है। सबसे पहले, ब्रॉडबैंड की भारतीय परिभाषा सर्वाधिक विकसित देशों की २ एमबीपीएस की तुलना में २५६ केवीपीएस है। दूसरे, शुद्ध बैंडब्रिथ का २५६ केवीपीएस भी अधिकांश डाटा एप्लीकेशंस के लिए पर्याप्त है बशर्ते कि उपयोगकर्ता को २५६ केवीपीएस बराबर मिलता रहे। दुर्भाग्य से, जब आईएसपी 'ब्रॉडबैंड' का वायदा करता है, वे उसी बैंडविड्थ का बहुविध उपयोगकर्ता के साथ पाइप का उपयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरुप भारत में अधिकांश उपभोगताओं को किए गये वादे में से उसका कुछ ही हिस्सा मिलता है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ब्रॉडबैंड को पुनर्भाषित करेगी जिसका अर्थ १:१ कन्टेंशन अनुपात सहित २ एमबीपीएस होगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए समृद्ध मीडिया

ब्रॉडबैंड की पुनर्परिभाषा प्रत्येक भारतीय के लिए यह सुनिश्चित करेगी–चाहें वह शहरों में हो या गांवों में – कि वह टेलिमेडिसिन नेटवर्क के माध्यम से सुदूर स्थान पर बैठे हुए भी डाक्टर से अपना 'चैकअप' करा सकें; एक–दूसरे के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग; और मांग करने पर टेलीविजन (IPTV) देख सकें। एक्सटेंशन अधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा जैसाकि स्कूल अध्यापकों को शिक्षा के प्राध्यापकों द्वारा किया जाता है। और यदि कानून अनुमति देता है तो गवाहों की गवाही भी ऑनलाइन ली जा सकेगी। इसकी असीम संभावनाएं हैं।

टेलीफोनी कवरेज का विस्तार

भाजपा चाहती है कि भारत के लोग अत्यन्त कम दरों पर टेलीफोनी के लाभ उठा सकें ताकि गरीब से गरीब लोग भी 'सम्पर्क' में रह सके। इसलिए भाजपा भारत टेलीकाम नियामक प्राधिकरण की सिफारिश से सहमत है कि वीओआईपी (VoIP) का क्रियान्वयन अबाधित हो। यदि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आती है तो वीओआईपी (VoIP) को कानूनी बनाया जाएगा और आवश्यक योजना तैयार करेगी। वीओआईपी साधारण जनता को राष्ट्रीय दूरी और अतंर्राष्ट्रीय दूरी की कॉलें, स्थानीय कॉल की दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

मोबाइल टेलीफोनी

भाजपा वादा करती है कि वह पांच वर्षों में मोबाइल उपभोक्ताओं की वर्तमान ४० करोड़ संख्या को १०० करोड़ तक लाने के लिए सही नीति अपनाएगी और ३जी (तीसरी पीढ़ी) मोबाइल नेटवर्क का क्रियान्वयन होने से अरबों उपभोक्ता न केवल वॉयस कॉल अपितु वीडियो कॉल भी कर सकेंगे।

ई–गवर्नेंस

- सभी पंचायतों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना।
- केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों में ''कागज रहित कामकाज''।
- गुजरात सरकार की 'ई-ग्राम विश्व ग्राम' योजना का देशभर में कार्यान्वयन।
- सूचना के अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) में नागरिकों से सम्बन्धित सभी सूचनाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने को एक अनिवार्य दायित्व (Duty to inform citizens) बनाकर नागरिकों को सूचना, चाहे वह मांगी भी न गई हों, देने के कर्तव्य को अतिरिक्त भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।

विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

''सरकार द्वारा दिए जाने वाले हरेक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लक्षित लाभार्थी तक पहुंच पाते हैं''

–1985 में उड़ीसा के सूखा प्रभावित कालाहांडी जिले के दौरे के समय एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की टिप्पणी

कांग्रेस की स्मॉल Pipeline (बीच में ही निधियों की हेराफेरी) की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की आई.टी. पाइपलाइन से निधियों के आवंटन में पारदर्शिता आयेगी और भ्रष्टाचार के लिए सजा की व्यवस्था होगी।

सुशासन के लिए ई-गवर्नेंस

भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सुशासन के मुद्दे का इतने जोरदार और प्रभावी ढंग से समर्थन नहीं किया है जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने। जब श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण-जयन्ती मनाने के लिए स्वर्ण जयंती रथयात्रा शुरू की थी, जनता के लिए उनका प्रमुख सन्देश यह था ''स्वराज का लक्ष्य पचास साल पहले प्राप्त किया गया था लेकिन सुराज का स्वप्न अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया है?''

जहां तक आम आदमी का सम्बन्ध है, सुशासन का अर्थ ईमानदार, भ्रष्टाचार-मुक्त, नागरिक हितैषी और सहयोगी शासन होता है। इसका अर्थ है कि नागरिकों का सम्मान हो, उनकी मांगें सुनी जाए और प्रशासन जनता के सेवक के रूप में व्यवहार करे न कि मालिक के रूप में। इस लक्ष्य को दूरगामी प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक और चुनावी सुधारों को लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी तंत्र की सोच में भी भारी परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त जरूरत है कि शासन में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता, किफायत, अभिनवता और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने १५ अगस्त, २००२ को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी। दुर्भाग्यवश, यू.पी.ए. सरकार के शासनकाल में इस योजना का कार्यान्वयन बुरी तरह से पिछड़ गया। भारतीय जनता पार्टी की भावी सरकार शासन के सभी स्तरों पर - केन्द्र सरकार से लेकर प्रत्येक पंचायत तक ई-गवर्नेंस को अत्यधिक व्यापक रूप में कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। हमारे विशिष्ट आश्वासन ये हैं-

- सरकार को देश के प्रत्येक नागरिक के द्वार पर ले जाना।
- सरकारी सेवाओं को प्रत्येक गांव और कस्बे में ऑनलाइन और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। यू.पी.ए. सरकार के १,००,००० सामूहिक सेवा केन्द्रों के अधूरे लक्ष्यों के मुकाबले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारत के प्रत्येक गांव में सामूहिक सेवा केन्द्रों की स्थापना करने का वादा करता है।
- सेवाएं मुहैया कराने में पारदर्शिता और सरकारी सेवकों की जवाबदेही निर्धारित करना।
- प्रत्येक नागरिक के लिए एक बैंक खाता खोलकर पूरा वित्तीय समावेशन। नागरिकों की देय राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते अधिमानतः घर की महिला के खाते में जमा की जाएगी।
- सरकार और नागरिक के बीच, सरकार और सरकार के बीच और सरकार और व्यवसाय के बीच सभी लेनदेन इलेक्ट्रोनिक तरीके से किए जाएंगे जिसका उद्देश्य कागजरहित सरकार की ओर अग्रसर होना है। शुरू में, कागजरहित कार्य संस्कृति केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों में शुरू की जाएगी।
- सूचना के अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) में नागरिकों से सम्बन्धित सभी सूचनाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने को एक अनिवार्य दायित्व (Duty to inform citizens) बनाकर नागरिकों को सूचना, चाहे वह मांगी भी न गई हों, देने के कर्तव्य के अतिरिक्त भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।
- भारतीय भाषाओं में विषय-सामग्री उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस का केन्द्र-बिन्दु होगा। सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विषय-सामग्री को हमेशा अद्यतन और संगत रखा जाए।
- नागरिकों को १-८०० बीएसएनएल का एक साधारण टोल फ्री टेलीफोन नम्बर उपलब्ध कराया जाएगा जो साल के २४ घण्टे x ७ दिन x ३६५ दिन उपलब्ध रहेगा ताकि वे अपने सांसदों से सम्पर्क कर सकें।

भगवान गणेश का भारतीय मानस में एक विशेष स्थान है क्योंकि उन्हें सभी बाधाओं के हर्ता के रूप में जाना जाता है। गणेश का मूषक (माउस) भगवान का सर्वव्यापी वाहन है। इसके आधुनिक अवतार में डिजिटल माउस एक ऐसा यंत्र है जिसे लोग सरकार से व्यवहार करने में परम्परागत बाधाओं को दूर करने के लिए अपने हाथों में रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाकर बाधा-मुक्त शासन मुहैया करायेगी।

''ई-ग्राम विश्व ग्राम'' : गुजरात की अग्रणी योजना को पूरे राष्ट्र में कार्यान्वित करने का भारतीय जनता पार्टी वादा करती है

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने प्रौद्योगिकी पर आधारित ग्रामीण सशक्तिकरण के एक नये युग की शुरूआत की है। यह योजना श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'सुराज' के लिए आह्वान के साथ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्मदिवस (२३ जनवरी, २००६) पर दक्षिणी गुजरात के हरिपुरा गांव से शुरू की गई। यह वही ऐतिहासिक गांव है जहां १९३८ में नेताजी ने 'स्वराज्य' का आह्वान किया था। महत्वाकांक्षी ई-ग्राम विश्व ग्राम परियोजना का लक्ष्य गुजरात की सभी १३, ६९३ ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। नेताजी के ''दिल्ली चलो'' के आह्वान के आधार पर मोदी ने गांवों के विकास के लिए ''गांव चलो'' का आह्वान किया।

'ई-ग्राम विश्व ग्राम' परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- ''पवन चैनल'' की शुरूआत - पंचायत का व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (Panchayat Wide Area Network)।
- सभी गांवों में ग्रामीण लोगों के लिए ई-उत्सव।
- ग्राम पंचायत विभिन्न विकास और कल्याण योजनाओं के लिए दस्तावेज और प्रमाण-पत्र, आवेदन पत्रों के फार्म जारी करेगी जिसमें ७/१२ प्रमाण-पत्र पंचायतों से किसानों को दिए जाएंगे।
- सभी गांवों में वीडियो कान्फ्रेसिंग और वीडियो ब्राडबैंड सुविधाएं।
- VSAT पर आधारित ब्राडबैंड कनेक्टिविटी।
- पंचायतों के मध्य निःशुल्क संचार व्यवस्था।
- किसानों को शिक्षा, टेलीमेडीसन, पशु चिकित्सा सेवाएं, बाजार सम्पर्क और कृषि से सम्बन्धित अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने, बिजली और टेलीफोन बिलों का भुगतान करने, मृत्यु तथा जन्म प्रमाण-पत्रों को जारी करने, भूमि स्वामित्व रिकार्ड रखने, डाक सेवाएं मुहैया कराने के लिए सामूहिक सेवा केन्द्र सुविधा।
- ग्रामीण लोग इन्टरनेट और साइबर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- बस और रेल टिकटों का आरक्षण और खरीद।

ई-ग्राम विश्व ग्राम से भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी क्योंकि सरकार और नागरिकों के बीच सभी लेन-देन का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। ज्योति ग्राम योजना के अन्तर्गत गुजरात के प्रत्येक गांव को २४ घण्टे और सातों दिन सफलतापूर्वक बिजली उपलब्ध कराने के बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत में पहली बार प्रत्येक गांव को ग्लोबल गांव (वैश्विक गांव) के साथ जोड़ने की एक परियोजना शुरू की है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को आधुनिक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ मिल सकें।

ई-गल्ला : किराना दुकानदारों का सशक्तिकरण

आई.आई.टी. मुम्बई की डेवलपमेंट इन्फोरमेटिक्स प्रयोगशाला-गल्ला छोटे दुकानदारों का नेटवर्क बनाने और उनके कार्यों (मुख्यतः स्टॉकिंग, बिलिंग और सीआरएम अथवा ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन) में सुविधा प्रदान करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का इस्तेमाल करती है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में न केवल रोजगार की सुरक्षा करना है बल्कि उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के लिए अच्छी परिस्थितियां पैदा करना है। जब वैश्विकरण ने भारत की असंगठित खुदरा दुकानों के समक्ष अनेक खतरे और चुनौतियां खड़ी कर दी हैं वहीं यह महत्वपूर्ण है कि भारत इस बड़ी संस्था को सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का इस्तेमाल करे जोकि खाद्य पदार्थों को ''आम आदमी'' तक पहुंचाने हेतु अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने में अत्यंत सस्ती और किफायती है। यह जरूरी है कि किराना स्टोर नेटवर्क की मजबूती का लाभ उठाया जाए-अर्थात ग्राहक आधार के बारे में इसके ज्ञान का इस्तेमाल करके आखिरी मील तक ग्राहक को जोड़ना तथा इस सेवा को लोकप्रिय बनाना। इस परिकल्पना को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट गल्ला ने छोटे दुकानदारों को लक्ष्य बनाते हुए प्रत्येक शॉप ऑटोमेशन साल्यूशन्स के लिए एसोसिएटिड सॉफ्टवेयर और मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस से जुड़ा विशेष प्रयोजन वाला एक समन्वित हार्डवेयर यंत्र तैयार किया है। इसके अलावा, छोटे दुकानदारों के लिए एक समन्वित वातावरण बनाना है ताकि वे साइबर स्पेस में एक समन्वित ढंग से अपने पदार्थों/वस्तुओं को प्रस्तुत कर सकें।

Agrocom (एग्रोकॉम) : आई.आई.टी. पर आधारित मौसम की भविष्यवाणी करने वाली प्रौद्योगिकी नासिक के अंगूर उत्पादकों की प्रति एकड़ एक लाख रूपये तक बचत करने में मदद करती है।

एग्रोकॉम एक स्टार्टअप कम्पनी है जो आई.आई.टी. मुम्बई के सौजन्य से चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोग हेतु ंुनं प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक सहयोग देने के अलावा, इसने छोटे मौसम केन्द्र (हरेक २५ कि.मी. की दूरी पर) स्थापित किए हैं जो एक अभिनव प्रणाली का हिस्सा है जो हमें तापमान, आर्द्रता और खेती स्तर पर फसल रोगों की भविष्यवाणी करने के उद्देश्य से पत्तियों की नमी, मौसम बीमा और निर्णय लेने में सहयोग हेतु मौसम की भविष्यवाणियों के लिए मौसम रिकार्ड वैद्यता जैसे उपाय मानकों की अनुमति देता है। एग्रोकॉम ने दिखाया है कि किसान नासिक घाटी में इसके ३० मौसम केन्द्रों से की गई फसल रोग भविष्यवाणियों का इस्तेमाल करते हुए १०-३० प्रतिशत तक अपनी लागत में बचत कर सकते हैं और साथ ही अपने कृषि उत्पादों में कीटनाशकों और रसायनों की मात्रा को कम कर सकते हैं। अंगूर उत्पादक दवाइयों के छिड़काव में कमी करके प्रति एकड़ १०,००० से एक लाख रूपये की बचत कर रहे हैं और कम लागत पर बेहतर गुणवत्ता की उपज प्राप्त कर रहे हैं।बाद वाला बिन्दु विशेषकर कृषि विशेषज्ञों के लिए निर्धारित कड़े अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों को देखते हुए ध्यान देने योग्य है।

aAqua (ए-एकुआ) : सूचना प्रौद्योगिकी किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विशेषज्ञ किसानों के उत्तर से कैसे मदद करती है

aAQUA एक चर्चा मंच है जो भारत की ग्रामीण आबादी को विभिन्न रूचिकर विषयों कृषि और पशुपालन से लेकर शिक्षा और उद्यमशीलता तक - से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मुम्बई द्वारा एक सहयोगपूर्ण प्रयास के रूप में महाराष्ट्र में कृषि विज्ञान केन्द्र और पुणे के पास पाबल में विज्ञान आश्रम शुरू किए गए जिनका उद्देश्य सुविज्ञ किसानों और ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रखने वाले किसानों के बीच सम्पर्क स्थापित करने हेतु प्रयास करना है। अप्रैल २००६ तक aAQUA पोर्टल को ७००० किसानों, किसान संगठनों, छोटे तथा मझोले कृषि व्यवसायों और बड़ी कम्पनियों के उपभोक्ताओं से १७००० से अधिक पोस्टें मिली हैं। भारत के ६०० से अधिक जिलों के २६० उपभोक्ताओं और विश्वभर के सदस्यों से प्रश्न प्राप्त हुए हैं। अनेक किसान विज्ञान केन्द्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ उपभोक्ताओं के प्रश्नों के उत्तर देते हैं।

एक विशिष्ट aAQUA चर्चा मंच में किसान समस्या बताता है और कृषि विशेषज्ञ अथवा अन्य किसान उसका समाधान करते हैं। फिलहाल उपभोक्ता वेबसाइट (www.aaqua.org) के माध्यम से या ई-मेल अथवा मोबाइल पर एसएमएस सन्देश भेजकर प्रश्न भेज सकता है। कोई भी गैर-व्यावसायिक उपभोक्ता मंच का निःशुल्क ब्राउज कर सकते हैं।

भूमि : किसानों को भूमि रिकार्ड आसानी से जारी कराना

यह किसी भी किसान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है जो उसकी भूमि जोतों : काश्तकारी और खेती के अधिकार (आर.टी.सी.) के रिकार्ड के बारे में सूचना का प्रमाण है। भूमि के लेन-देन, फसल, ऋण तथा भूमि जोतों के आकार से जुड़ी रियायतें प्राप्त करने हेतु राइट टेनेंसी एण्ड कल्टीवेशन (आर.टी.सी.) की जरूरत पड़ती है। मैनुअल प्रणाली में यह रिकार्ड गांव के लेखपाल (पटवारी) द्वारा रखे जाते हैं जो प्रायः शोषक माने जाते हैं। चूंकि इन रिकार्डों की कोई सार्वजनिक संवीक्षा नहीं होती है इसलिए इनमें हेराफेरी की काफी गुजांइश रहती है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार जब सत्ता में थी, तो इसने भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण को पूरा करने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करने में कर्नाटक सरकार (उस समय कर्नाटक में कांग्रेस का शासन था) की मदद की थी। 'भूमि' नामक योजना से भूमि रिकार्डों का आसानी से रख-रखाव करने और उन्हें तीव्रता से अद्यतन बनाने; और भूमि रिकार्डों में हेराफेरी को रोकने में मदद मिलती है; किसानों को आसानी से अपना भूमि रिकार्ड देखने की सुविधाएं होती हैं; अदालतों, बैंकों, निजी संगठनों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा डाटाबेस तैयार करने में आसानी होती है। कर्नाटक में आर.टी.सी. जारी करने का समय अनेक दिनों से घटकर लगभग १५ मिनट हो गया है। इस योजना के सन् २००० में शुरू होने से लेकर लगभग दो करोड़ उपभोक्ताओं ने इसका इस्तेमाल किया है।

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना में काफी सुधार किया है ताकि इसे और भी किसानों के अनुकूल बनाया जा सके।

ई–बैंकिग

- सभी नागरिकों का बैंक में खाता होगा
- सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले सभी वित्तीय लाभों को सीधे लाभार्थी अधिमानतः घर की महिला के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

डिजीटल क्रांति

ई–डेवलपमेंट

- किसानों को वांछित सूचनाएं (मार्केट, लागत, कृषि कार्यों, सरकारी योजनाओं इत्यादि के बारे में) डिजीटल प्लेटफॉर्म- ई मंडी, एग्रोपेडिया, सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.) पर आधारित कृषि-क्लीनिक इत्यादि
- कला, शिल्प और अनौपचारिक क्षेत्र, छोटे और मझोले उद्यमों, अन्य क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करना।
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन) ताकि पांच वर्षों में कुशल कारीगरों की संख्या ८ प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत की जा सके
- संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल।
- जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों (ग्रीन टेक्नालॉजी) का प्रयोग।

डिजीटल क्रांति

सभी के लिए ई-विकास

आज हम वास्तव में एक वैश्विक ग्राम में रहते हैं। लेकिन यह एक ''गांव'' भी है जिसकी आबादी सूचना ''उपलब्ध'' वाले अमीरों और अधिक बहुसंख्यक सूचना ''अनुपलब्ध'' वाले गरीबों के बीच बटी हुई है। यह भारत और विश्व दोनों के लिए सच है। यह डिजीटल विभाजन घनिष्ठ रूप से सामाजिक-आर्थिक विभाजन के समान है। भारतीय जनता पार्टी इस विभाजन को अस्वीकार्य मानती है और इस विभाजन को जितना भी अधिक से अधिक कम किया जा सके, घटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु नीतियां और रणनीतियां तैयार करेगी :

- सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करना, जिसमें करोड़ों लोग गरीबी से ऊपर उठेंगे और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सुरक्षित आजीविका मुहैया कराई जाएगी। भारत के पास गरीबी, भुखमरी और अल्प-रोजगार की दुखद स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं बशर्ते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार सृजन, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, शिक्षा और पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देने के उपायों को जोरदार ढंग से कार्यान्वित करने की राजनीति इच्छा-शक्ति हो। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा करने के लिए इच्छा-शक्ति और दृष्टिकोण है।
- भारत में सरकार द्वारा वित्त-पोषित विकास परियोजनाओं लिए भ्रष्टाचार अभिशाप रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की नवीनतम रिपोर्ट में गंभीर रूप से दर्शाया गया है कि यू.पी.ए. सरकार इस बात का सही लेखा-जोखा नहीं दिखा रही है कि वर्ष २००७-०८ में विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए आवंटित की गई लगभग ५१,००० करोड़ रूपये की धनराशि किस तरह से खर्च की गई? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की भावी सरकार केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं और पंचायतों को निरन्तर जोड़ने हेतु एक ठोस सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का आधारभूत ढांचा खड़ा करेगी ताकि सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। जो लोग सरकारी निधियों की हेराफेरी के लिए जिम्मेदार पाए जायेंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
- वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से प्रत्येक नागरिक का एक बैंक खाता होगा और उसमें लाभार्थियों को मिलने वाली कल्याण निधियां सीधे उसके खाते में हस्तांतरित की जाएंगी।
- प्रत्येक बीपीएल परिवार को एक निःशुल्क स्मार्ट मोबाइल टेलीफोन दिए जाएंगे जिसका निरक्षर लोग भी अपने बैंक खाते तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना और अन्य गरीबी निवारण योजनाओं में धन की हेराफेरी को रोकने में मदद मिलेगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) पर आधारित विकास के वृहद् ढांचे में लैंगिक न्याय और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय को सम्मिलित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के उपयोग का सार्वभौमिकरण। भारत का आई.टी. और आई.टी. ई.एस. उद्योग जिसका अभी तक ध्यान विदेशी बाजारों से व्यवहार करने पर रहा है, को घरेलू अर्थव्यवस्था में योगदान देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा भारत की रणनीतिक जरूरतें हैं। हम दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों वाली नीतियां तैयार करेंगे और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।
- जलवायु परिर्वतन के मुद्दों का आई.टी. के अभिनव उपयोगों से समाधान किया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भावी सरकार के समक्ष दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा-भारत और चीन के बीच डिजिटल विभाजन को मिटाना (नीचे तालिका देखें)। हम अगले पांच वर्षों में भारत को प्रत्येक आई.टी. पैरामीटर में चीन के बराबर लाने के लिए कृत-संकल्प हैं।

पैरामीटर (करोड़ों में)	भारत	चीन
पर्सनल कम्प्यूटरों की संख्या	2.8	16.2
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या	0.54	8.5
इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या	5.2	29.8
मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या	40	65

ई–एजुकेशन

- प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में इंटरनेट पर आधारित शिक्षा दी जाएगी
- संस्थाओं और उद्योग के ज्ञान (नॉलेज) को परस्पर जोड़ा जाएगा
- सभी भारतीय भाषाओं (विकीपीडिया, यू-ट्यूब आदि) में वेब पर आधारित ओपन सोर्स शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे
- अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विषय में तैयार सर्वोत्तम लेक्चर्स का राष्ट्रीय कोष बनाया जाएगा
- २५ लाख नये अध्यापकों के लिए नौकरियों के अवसर सृजित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा
- आई.टी. पर आधारित ओपन और दूरस्थ शिक्षा प्रद्धति का विस्तार किया जाएगा

10000 रूपये का लेपटॉप

- कम से कम एक करोड़ विद्यार्थियों को १०००० रूपये की कीमत पर पूरी तरह से लोडेड लेपटॉप (२ जीबी रैम के साथ कोर २ डुयो प्रोसेसर) मिलेंगे
- जो विद्यार्थी लेपटॉप नहीं खरीद सकते उन्हें लेपटॉप खरीदने के लिए बिना ब्याज के ऋण दिए जायेंगे
- सभी लेपटॉपों को चलाने के लिए फ्री, ओपन सोर्स, सॉफ्टवेयर मुहैया कराये जायेंगे

ई-शिक्षा

10,000 रूपये का लेपटॉप और अन्य सपनों को पूरा करना

भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमें डिजिटल क्रांति को संभव बनाने हेतु कम्प्यूटर परिसम्पत्ति - हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित मानव संसाधन- की मांग पैदा करने और उनकी घरेलू आपूर्ति करने की जरूरत है। इस बात को समझते हुए कि सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) पर आधारित शिक्षा ने शिक्षण और अध्ययन दोनों में क्रांति ला दी है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी में छिपी हुई क्षमता बाहर आई है, हमारी पार्टी स्वयं ई-शिक्षा के बुनियादी साधन-इंटरनेट कनेक्शन सहित लेपटॉप कम्प्यूटर-को भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए खरीदने की क्षमता योग्य बनाने का वादा करती है। इसलिए, स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को १०,००० रूपये और उससे भी कम कीमत पर कम से कम एक करोड़ अत्याधुनिक लेपटॉप (कोर २ डुओ अथवा एक्यूवेलंट प्रोसेसर; २ जीबी रेम; २५० जीबी हार्ड डिस्क; विल्टइन २ मेगापीक्सल वेबकॉम, माइक्रोफोन और स्पीकर्स; वाईफाई और ब्ल्यूटूथ सुविधाएं तथा एक १३ इंच की स्क्रीन) उपलब्ध कराने का हमारा वादा है। लेपटॉप एक कम्प्यूटर है जिसे हम बढ़ावा देना चाहते हैं।

आजकल बाजार में इस तरह के लेपटॉप की कीमत ३५,००० रूपये से अधिक है। यह १०,००० रूपये की कीमत पर कैसे उपलब्ध होगा? इसका उत्तर सीधा है। हमने देखा है कि घरेलू विनिर्माण से जुड़ी मांग ने मोबाइल फोन की कीमत घटा दी है जो अब आम आदमी की पहुंच में आ गया है इसलिए हमारी सरकार लेपटॉपों और उनके पुर्जों का भारत में घरेलू विनिर्माण (उनकी केवल असेम्बलिंग ही नहीं) करने पर बल देगी। इससे भारत में आई.टी. विनिर्माण उद्योग के लिए एक ठोस नींव भी पड़ेगी।

१०,००० रूपये का लेपटॉप का सपना प्री-लॉडिड कमर्शियल सॉफ्टवेयर से पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार प्रचालन प्रणाली (ऑपरेटिंग सिस्टम) सहित मुक्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगी। इससे विद्यार्थी समुदाय में कुछ नया करने की आदत भी पडेगी।

कक्षाओं तक ई-शिक्षा को बढ़ावा, भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में वेब पर आधारित शिक्षा देने का वादा करती है। इससे कम से कम २५ लाख नये कम्प्यूटर अध्यापकों और विभिन्न भारतीय भाषओं में आई.टी. कोर्सवेयर के सृजकों (क्रियेटर्स) के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, एक यूजर जेनरेटेड राष्ट्रीय ज्ञान भण्डार (विकीपीडिया की तरह) और एक यूजर जेनरेटिड वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म (यू-टयूब की तरह) भी उपलब्ध होगा। विशेषकर उच्चतर शिक्षा के लिए, शीर्ष संस्थानों के अग्रणी शिक्षाविदों द्वारा दिए गए सर्वोत्तम भाषणों (लेक्चर्स) का ऑनलाइन भण्डार भी उपलब्ध होगा। उदाहरण के लिए, आई.आई.टी. बम्बई की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के शासनकाल में हुई थी ताकि टेली कम्यूनिकेशन के जरिए इंजीनियरिंग कालेजों के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आई.टी. पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा सके। संक्षेप में, हमारी सरकार भारत में ज्ञान क्रांति को तेज करने हेतु 'रोटी, कपड़ा और मकान' की तरह उच्च प्राथमिकता के आधार पर आई.टी. पर आधारित शिक्षा को आगे बढ़ायेगी।

हमारी सरकार उच्चतर शिक्षा में वर्तमान में विद्यार्थियों की ११ प्रतिशत की कुल नामाकंन दर को पांच वर्षों में बढ़ाकर २० प्रतिशत करने के लिए दूरस्थ शिक्षा और ओपन विश्वविद्यालय के मॉडलों का इस्तेमाल करेगी। चीन में विद्यार्थियों की कुल नामांकन दर ३० प्रतिशत से ऊपर है। हमारी सरकार की दूसरी प्राथमिकता होगी - भारत के अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र के लगभग ६५ प्रतिशत कार्यबल जिनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, का दूरस्थ शिक्षा और ओपन यूनिवर्सिटी मॉडलों का इस्तेमाल करके आई.टी. पर आधारित कौशल विकास करना। इस क्षेत्र में चुनौती के आकार को इस तरह से आंका जा सकता है कि भारत में ८ प्रतिशत कार्यबल के मुकाबले दक्षिण कोरिया में ६६ प्रतिशत कार्यबल, जर्मनी में ७५ प्रतिशत और जापान में ८० प्रतिशत कार्यबल को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है। इसके अलावा, भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) की संख्या को ५,००० से बढ़ाकर ५०,००० (चीन में ५,००,००० संस्थान हैं) करने हेतु हमारी सरकार कौशल विकास को एक मिशन के रूप में कार्यान्वित करने हेतु बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को शामिल करेगी।

ई–भाषा

- भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय मिशन की स्थापना
- भारत में बेचे जाने वाले सभी साफ्टवेयर २२ राजभाषाओं के अनुरूप बनाये जायेंगे

इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा रोजगार गहन भाषा उद्योग सृजित होगा

ई-भाषा

भारतीय भाषाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में उचित स्थान दिलाना

सूचना प्रौद्योगिकी का मोबाइल, कम्प्यूटर (पी.सी.) और टी.वी. जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए विश्वभर में लाभ उठाया जा रहा है। प्रौद्योगिकियों के विकास ने इंटरनेट को सभी को आपस में जोड़ने और उपभोक्ताओं को विश्व में किसी भी समय और कहीं पर भी अपने उपयोग के लिए विविध प्रकार की सामग्री प्राप्त करने हेतु एक महासमुद्र के रूप में समर्थ बनाया है। तथापि, भारत में आई.टी. के शीघ्र विकास में सबसे बड़ी बाधा भारतीय भाषाओं में आई.टी. को स्थानिक बनाने की है। हमारे देश में आई.टी. का मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में ही प्रचलन होता है जो हमारी १० प्रतिशत से भी कम जनसंख्या द्वारा समझी जाती है। चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों ने यह सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है कि उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में भी उतने ही प्रवीण हैं।

भारतीय जनता पार्टी भारत में आई.टी. के विकास में भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे होने वाले प्रचुर आर्थिक लाभों के अलावा, यह उपभोक्ता का ''सामाजिक स्तर'' भी बढ़ायेगी; उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनायेगी; उनकी भाषा और कलात्मक एवं साहित्यिक धरोहर को समृद्ध बनाएगी तथा राष्ट्रीय एकता में योगदान देगी।

यद्यपि भारतीय लिपियां अलग-अलग दिखाई देती हैं लेकिन सूचना एकान्तरण के लिए भारतीय मानक संहिता एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में विषय-सामग्री का तत्काल ''लिप्यन्तरण'' (ट्रांसलिटरेशन) प्रस्तुत कर देती है। इसी प्रकार, इन्सक्रिप्ट की-बोर्ड से कॉमन कीज (keys) का इस्तेमाल करते हुए सभी भारतीय भाषाओं में टाइपिंग की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भावी सरकार निम्नलिखित विशिष्ट उपायों के साथ विभिन्न प्रचलित माध्यमों के जरिए सभी २२ अधिकारिक भाषाओं में आई.टी. के विकास हेतु एक राष्ट्रीय ई-भाषा आयोग शुरू करेगी :

- भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल में सबसे बड़ी दिक्कत डिसप्ले की नहीं बल्कि टाइपिंग की है। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हुए भारतीय भाषाओं में टाइप करने से काफी ध्वन्यात्मक (Phontic) और वर्तनी (Spelling) की त्रुटियां रह जाती हैं जिससे व्यक्ति इसका इस्तेमाल करने में हतोत्साहित हो जाता है। सरकार विनिर्माताओं के लिए भारतीय भाषा में छपे की-बोर्ड बनाना अनिवार्य करेगी।
- सभी भाषाओं में अनेक कलात्मक फोन्ट्स का विकास जिनका अंग्रेजी की तरह आपस में इस्तेमाल (इन्टरओपरेट) किया जा सके। इस तरह, भारतीय भाषाओं में वर्ड प्रोसेसिंग, ब्लागिंग और प्रकाशन (पब्लिशिंग) अंग्रेजी की तरह ही आसान और कलात्मक हो जाएगा। लिखावट (हेंडराइटिंग) में सुधार हेतु सॉफ्टवेयर पैकेज को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- भारतीय भाषाओं के शिक्षण उपकरणों को सॉफ्टवेयर में अंतःस्थापित करके स्कूली बच्चों को उनके इस्तेमाल में प्रवीण बनाना। डिजिटल शब्दकोषों, विश्वकोषों और व्याकरण जांचकर्ता, एनिमेशन गेम्स जैसे शिक्षण उपकरणों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
- विभिन्न कक्षाओं के लिए विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे विभिन्न विषयों हेतु भारतीय भाषाओं में डिजिटल कोर्सवेयर का विकास।
- यू-ट्यूब और विकीपीडिया जैसे ऑनलाइन विश्वकोष की वीडियो शेयरिंग साइटों का निःशुल्क इस्तेमाल करने की सुविधा होने से अब यह संभव हो गया है कि विद्यार्थी विश्वभर में ज्ञान के प्रचुर भण्डार से लाभ उठा सकते हैं। हमारी सरकार भारतीय भाषाओं में ऐसे संसाधनों के विकास में मदद देगी।
- मोबाइल फोनों के विनिर्माताओं से भारतीय भाषाओं में संदेशों के भाषान्तर को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा की जाएगी।
- आई.टी. के लाभों को हरेक व्यक्ति तक पहुंचाने का सर्वोत्तम माध्यम टी.वी. है। टी.वी. माध्यम न केवल सभी भौगोलिक क्षेत्रों में हरेक व्यक्ति तक पहुंचता है बल्कि इसके कार्यक्रम प्रमुखतः भारतीय भाषाओं में होते हैं। हमारी सरकार डीटीएच सेवा प्रदाताओं और सेटटॉप बॉक्स और रिमोट कंट्रोल निर्माताओं के लिए भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना अनिवार्य करेगी। इससे टी.वी. और फिल्मों की सर्वोत्तम सामग्री को बहुभाषायी उप-शीर्षकों में उपलब्ध कराया जा सकता हैं।
- संस्कृत के ऑनलाइन शिक्षण और अध्ययन को प्रोत्साहन जिसकी स्वतंत्र भारत में काफी समय से उपेक्षा की गई है।
- अंधे और गूंगे-बहरे लोगों के इस्तेमाल के लिए सभी भारतीय भाषाओं में विशेष सॉफ्टवेयर का विकास। इससे उन्हें कौशल पर आधारित शिक्षा तथा रोजगार के बराबर के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

ई–हेल्थकेयर

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक अस्पताल और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य-देखभाल केन्द्र को नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस नेटवर्क से जोड़ना
- प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य रिकार्ड रखा जाएगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए सभी नागरिकों के लिए एक बुनियादी स्वास्थ्य बीमा योजना
- आयुर्वेद और योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- ग्रामीण बस्तियों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित घूमती-फिरती चिकित्सा- उपचार वैन (मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन्स)
- सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) पर आधारित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार

डिजीटल क्रांति

ई-हेल्थकेयर

भाजपा के लिए टेलीमेडिसिन क्यों उच्च प्राथमिकता है

बंगलुरू के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ सर्जन डा० देवी शेट्टी ने भारत में टेलीमेडिसिन की संभाव्यता की व्याख्या इन शब्दों में की थी – ''रोग प्रबन्धन में ६६ प्रतिशत यह संभावना होती है कि बीमार व्यक्ति को ऑपरेशन की जरूरत न पड़े। और जब ऑपरेशन की जरूरत नहीं हो तो आप मरीज को छुए बगैर भी चिकित्सा कर सकते हैं। आपका वहां मौजूद रहना जरूरी नहीं है आप कहीं भी रह सकते हैं क्योंकि कोई भी निर्णय रोग प्रबन्धन में मरीज के रोग इतिहास और क्लीनिकल जांच के आधार पर लिए जाते हैं..... लिहाजा, ६६ प्रतिशत स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का टेलीमेडिसिन से जुड़े दूर बैठे डॉक्टरों के जरिए समाधान किया जाना संभव है।''

टेलीमेडिसिन ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण दूर-दराज के क्षेत्रों में अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को शहरी क्षेत्रों के आधुनिक तकनीक से युक्त अस्पताल के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से लांच किए गए टेली कम्यूनिकेशन सेटेलाइट के जरिए संभव हो रहा है। ग्रामीण अस्पताल में टेलीविजन, मॉनीटर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ मूलभूत डायग्नोस्टिक उपकरण उपलब्ध किए जाते हैं। इन उपकरणों के जरिए ग्रामीण अस्पताल के मरीजों का स्वास्थ्य रिकार्ड एडवांस में विशेषज्ञ डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाता है और वे मरीज व उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश देते हैं और पालन करने हेतु उपचार बताते हैं।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट का उद्घाटन जुलाई २००२ में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था जिसे पोर्ट ब्लेयर के जी.बी. पंत अस्पताल और चेन्नई के श्री रामचन्द्र मेडीकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट से जोड़ा गया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि टेलीमेडिसिन और दूरस्थ शिक्षा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के भारतीय स्पेस वैज्ञानिकों का योगदान सैन्य उपयोग से कहीं ज्यादा रहा है।

भारत में स्वास्थ्य-देखभाल के लिहाज से काफी असंतुलन है। यद्यपि लगभग ७५ प्रतिशत भारतीय लोग गांवों में रहते हैं जबकि ७५ प्रतिशत से अधिक डॉक्टर शहरों में रहते हैं। ७० करोड़ में से अधिकांश भारतीयों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के ८६ प्रतिशत मरीजों को जरूरी उपचार के लिए करीब ८ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। दूरवर्ती इलाकों में तो समस्या और भी विकट है। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच खाई को पाटने के लिए टेलीमेडिसिन एक शीघ्र और सस्ता तरीका है। योजना आयोग के अनुसार, भारत में इस समय ६ लाख डॉक्टरों, १० लाख मिलियन नर्सों और २ लाख डेन्टल सर्जनों की कमी है। प्रति १० हजार भारतीयों के ऊपर मुश्किल से सिर्फ एक डॉक्टर है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य-देखभाल के बीच अंतर को पाटने के लिए टेलिमेडिसिन सबसे सस्ता और तीव्रतम तरीका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भाजपा के नेतृत्व वाली भावी सरकार उपचारी और सामुदायिक स्वास्थ्य-देखभाल सेवा को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगी। यह आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य परम्परागत भारतीय पद्धतियों, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देगी। भारत में पशुधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ग्रामीण जनसंख्या के लिए यह आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दुःख की बात है कि भारत में पशु चिकित्सा की पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का इस अभाव को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

ई–रिकॉर्ड

- सभी मंत्रालय के सरकारी रिकार्डों को डिजिटल बनाया जाएगा
- जमीन और सम्पत्तियों के सभी रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा
- नागरिकों के दूसरे सभी रिकार्ड (जन्म, विवाह, मृत्यु आदि) ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे
- राष्ट्रीय पाण्डुलिपी मिशन जो वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया था, को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा
- भारत की अमूर्त परम्परा (संगीत, मौखिक इतिहास, लोक कला आदि) के संरक्षण के लिए आई.टी. उपकरणों का प्रयोग करते हुए इसी तरह का मिशन शुरू किया जाएगा

अभिलेख (ई-रिकार्ड)

भौगोलिक अभिलेख (रिकार्ड): यद्यपि भारत का इतिहास पांच हजार वर्षों से ज्यादा प्राचीन है परन्तु एक राष्ट्र के रूप में हमने ऐतिहासिक और आधुनिक अभिलेखों को सही से रखने का काम नहीं किया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) ने अब अभिलेखों विशेषकर आर्थिक विकास के आंकड़ों के संरक्षण, वर्गीकरण और व्यावहारिक उपयोगिता के लिए प्रभावी उपकरण उपलब्ध करा दिया है।

भू-आकाशीय और भू-आर्थिक आंकड़े बेहतर आर्थिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित डिजिटल आंकड़े बड़ी संख्या में फैले सार्वजनिक निकायों द्वारा वेब पर आधारित ट्रेवल सर्विस से लेकर आवास निर्माण हेतु छोड़ी गई जमीन की सुस्पष्ट पहचान करने तक; सार्वजनिक उपयोगिताओं (जैसे सीवेज और वॉटर पाइप लाइनों) से लेकर नगरपालिका और पंचायत निकायों की सम्पत्ति में बढ़ोतरी करने तक; और शहरी यातायात को नियंत्रित करने से लेकर अपराध रोकने में पुलिस की सहायता करने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। निजी क्षेत्र भी इस डाटा का अनेक तरह से - जैसे लक्षित मार्केटिंग से लेकर बीमा जोखिम की गणना करने तक और मोबाइल फोन पर स्थान - आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने से लेकर कार में नेविगेशन और यातायात की लॉजिस्टिक प्रणाली विकसित करने तक - में उपयोग कर सकता है।

दुर्भाग्य से भारत ने अभी तक समग्र जीआईएस आधारित सेवाओं की संभावनाओं को पहचाना नहीं है। इसलिए भाजपा सर्वे ऑफ इण्डिया को पुनर्जीवंत और इसे मात्र नक्शे बनाने वाली संस्था से (क) २४ x ७ ऑनलाइन भू-सूचना प्रदाता और (ख) भूमि तथा सम्पत्ति अभिलेखों को मानक बनाने वाली संस्था के रूप में परिवर्तित करने की योजना रखती है। एक भू-सूचना प्रदाता के रूप में सर्वे ऑफ इण्डिया एक भू-आकाशीय डाटा फ्रेमवर्क सृजित करेगा जिसमें भारतीय भू-भाग का प्रत्येक वर्ग मीटर मापा, चिन्हित और संदर्भित किया जाएगा और सर्वे ऑफ इण्डिया, इसरो के भुवन प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम करेगा जो अन्य आर्थिक आंकड़ों के साथ सेटेलाइट चित्रों को मिलाएगा। मानक स्थापित करने वाले एक निकाय के रूप में यह भूमि और सम्पत्ति अभिलेखों के लिए डिजिटल वास्तुशिल्प तैयार करेगा।

भूमि और सम्पत्ति अभिलेख: भारत सरकार स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराएगी ताकि वे भूमि और सम्पत्ति के रिकार्डों का डिजिटाइजेशन पूरा कर सकें। भाजपा की योजना एक प्रभावी भूमि पंजीकरण प्रणाली और आसानी से उपलब्ध एक भूमि रिकार्ड प्रणाली की है जो सम्पत्ति कारोबार में विश्वास जगा सके।

धरोहर अभिलेख (हेरिटेज रिकार्ड): राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, आधुनिक काल की राष्ट्रीय दीर्घा और अन्य प्रदेश स्तरीय संग्रहालय - भारत में प्रमुख रिकार्ड रखने वाले, ज्ञान और सांस्कृतिक पहलुओं को संजोने वालों में हैं। इन सभी संस्थाओं का आधुनिकीकरण और इनके संग्रह को ऑनलाइन प्रदर्शित करने को प्रोत्साहित करते हुए भाजपा का इरादा एक नया राष्ट्रीय डिजिटल अभिलेखागार और पुस्तकालय (National Digital Archive & Library) गठित करने का है जो (क) हमारी जानकारियों, ज्ञान और धरोहर स्रोतों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा और (ख) तात्कालिक तथा भविष्य की जन-सूचनाओं के अभिकरण का एक ढांचा तैयार करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, बायो-विविधता और कला, संस्कृति, वास्तुकला आदि में इसकी मूल्यवान धरोहर के भारत के परम्परागत ज्ञान को संरक्षित करेगी।

राष्ट्रीय डिजिटल अभिलेखागार और पुस्तकालय (एनडीएएल) में राष्ट्रीय अभिलेखागार की सभी सामग्री जोकि अतीत में 'वर्गीकृत' श्रेणी में थी, साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तकें और लिखित सामग्री जिसका कॉपीराइट समाप्त हो गया है - शामिल की जाएंगी। राष्ट्रीय डिजिटल अभिलेखागार और पुस्तकालय पीआईबी, इसरो, डीआरडीओ आदि सरकारी संस्थाओं द्वारा संग्रहित की गई सभी सार्वजनिक फोटोग्राफी के संग्रह को भी अपने में समाहित करेगा। अंततः वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन पुनर्जीवित किया जाएगा और इसके संग्रह को ''एनडीएएल'' द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।

ई–जस्टिस

- संविधान के अनुच्छेद २१ में शीघ्र न्यायिक सुनवाई के अधिकार का उल्लेख किया गया है : इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति नगण्य है :
- आज ई-जस्टिस से अभिप्राय है :
  - पिछले रिकार्डों को डिजीटल बनाना
  - वर्तमान मामलों की सूची तैयार करना
  - न्यायिक अधिकारियों को लेपटॉप उपलब्ध कराना
- ई-जस्टिस को न्यायिक प्रक्रियाओं - स्वचलन के रूप में नहीं - बल्कि बड़ी संख्या में बचे न्यायिक मामलों को निपटाने के रूप में देखा जाना चाहिए

ई-जस्टिस

न्याय उपलब्ध कराना

विधि और न्यायिक सुधार करके ''सभी के लिए न्याय'' दिलाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। लोकतंत्र की शक्ति को न्यायपालिका द्वारा नागरिकों को न्यायसंगत, शीघ्र और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता और कानून का शासन लागू करने की योग्यता से आंका जाता है। भारत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों जिनसे न्याय उपलब्ध कराने में काफी विलम्ब होता है, के ढेर को निपटाने की जरूरत एक उच्च प्राथमिकता है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुधार करने से न्यायिक प्रशासन की गुणवत्ता (क्वालिटी) और कार्यकुशलता में सुधार होगा; कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाया जा सकेगा; न्यायाधीशों को और अधिक स्वतंत्रता मिलेगी तथा उनकी जबाबदेही बढ़ेगी; न्यायालयों की भौतिक सुविधाओं का विकास होगा; नागरिकों की कानूनी जानकारी बढ़ेगी; वकीलों के मानकों में सुधार आयेगा; और गरीबों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों की न्याय प्राप्त करने तक पहुंच बढ़ेगी। इसके आलावा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों जिन्होंने अब अधिक आसान किफायती, पारदर्शी, शीघ्र और नागरिक हितैषी तरीके से जनता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, की न्यायिक प्रणाली के साधनों को सभी स्तरों पर लागू करने की जरुरत है।

इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भावी सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी :

- जजों को अपनी सम्पत्तियों का नियमित आधार पर ब्यौरा देने के लिए कानून बनाया जाएगा और उससे जुड़ी सूचना को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
- न्यायालय से संबन्धित सभी रिकार्डों और पंजीकरण के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण जिनकी आसानी से खोज हो सके। इससे न्यायालयों के बीच, राज्यों आदि के बीच इसी तरह के मुकदमेबाजी के मामलों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी।
- न्यायालय के फैसलों का कम्प्यूटरीकरण जिससे निर्णयों का मानकीकरण होगा।
- न्यायालयों के कलेंडरों का कम्प्यूटरीकरण जिससे न्यायालयों में मामलों की बार-बार तारीखें बदलने में कमी आयेगी और नागरिकों को अनावश्यक रुप से न्यायालयों के चक्कर काटने से बचाया जा सकेगा।
- वकीलों के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण जिससे न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
- न्यायालय, पुलिस, जेल और म्युनिसिपल रिकार्डों (जन्म, मृत्यु, विवाह आदि) तक जनता की आसानी से पहुंच।
- त्वरित और सुरक्षित न्यायतंत्र हेतु वीडियो कांफ्रेंसिग का उपयोग।
- नागरिकों में विधिक साक्षरता को प्रोत्साहन जिसे आसानी से समझ में आने वाली स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
- जुर्माने, कोर्ट फीस, निर्वाह-भत्ते, बच्चे के पालन-पोषण खर्च का ऑनलाइन भुगतान।
- लोक अदालतों, विधिक सेवा प्राधिकरणों की सहायता, मानवाधिकार आयोग और विभिन्न नागरिक सामाजिक संगठनों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्रों को प्रोत्साहन।
- डिजिटल पुस्तकालयों, डाटाबेसों, केस मैनेजमेंट प्रणालियों और न्यायिक प्रशासनिक पद्धतियों के माध्यम से विश्व के सर्वोत्तम कार्य-व्यवहारों को अपनाना तथा सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा।

महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की समस्याओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। तदनुसार, आई.टी. का उपयोग भूमि से सम्बन्धित कानूनों, महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रक्षा करने वाले कानूनों, श्रमिक कानूनों और रोजमर्रा के जीवन में आम आदमी को प्रभावित करने वाले सामान्य कानूनों के अनुपालन में तेजी लाई जाएगी। दृष्टिकोण यह है कि आई.टी. के माध्यम से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराया जाएगा; संविधियों को लागू करने में शामिल सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी; कानूनी सहायता केन्द्रों, विधि सेवा प्राधिकरण जैसी विभिन्न सहायता एजेंसियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं (कांउसिलर्स) और आम नागरिकों से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा।

ई–सेफ्टी

- आपदा नियंत्रण और प्रबन्धन के लिए आई.टी. का इस्तेमाल
- रेलवे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन
- सड़कों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन

डिजीटल क्रांति

ई-सेफ्टी

भारतीय जनता पार्टी हमारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष २००१ में आए भयंकर भूकंप को देखते हुए वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (नेशनल डिसास्टर मैंनेजमेंट अथॉरिटी) की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करने हेतु एक व्यापक समिति गठित की थी। इस समिति की सभी सिफारिशों को वर्ष २००३ में स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार द्वारा की गई तैयारी से वर्ष २००५ में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम को प्रस्तुत करने में यूपीए सरकार को मदद मिली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की भावी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का उपयुक्त इस्तेमाल करके राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम की कार्य-प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी।

हम एक केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित और संचालित राष्ट्रीय आपात सेवा (एनईएस) सृजित करेंगे। राष्ट्रीय आपात सेवा (एनईएस) की भूमिका पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग पॉइन्ट्स नामक सम्पर्क केन्द्रों का एक देशव्यापी जाल बिछाना होगा जो सभी स्थानीय पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए इन्टरफेस के एक एकल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। कोई व्यक्ति जो आपात स्थिति में फंसा हुआ है, एक राष्ट्रीय तौर पर एकमात्र नम्बर (उदाहरण के लिए १२३) डायल कर सकेगा और निकटस्थ पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग पॉइन्ट्स (पीएएसपी) को टेलीफोन कर सकता है जो तत्काल मदद भेजने के लिए स्थानीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित करेगा।

राष्ट्रीय आपात सेवा (एनईएस) का इस्तेमाल उन विशेष क्षेत्रों के लोगों को आपात स्थिति की चेतावनी को प्रसारित करने, टेलीफोन करने और एसएमएस भेजने के लिए भी किया जा सकता है जो किसी खास संकट में फंसे हुए हैं (उदाहरण के लिए वर्ष २००४ में आया सुनामी)।

रेल और सड़क सुरक्षा

रेलवे, भारत में राष्ट्रीय एकता और आर्थिक वृद्धि का मुख्य स्रोत रहा है। दुःखद बात यह है कि अतीत में रेलवे सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सन् २००३ के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रेलवे सुरक्षा के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने की घोषणा की थी। यह मिशन भारतीय रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आइ.आई.टी. कानपुर और निजी क्षेत्र की कम्पनियों की भागीदारी से शुरु किया गया।

इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों में शामिल था-(i) सुरक्षा और नियंत्रण तकनीक का विकास और उसे अपनाना जिसका उद्देश्य उच्च संचलन, संचरण की निम्न कीमत और सुरक्षित रेलवे यातायात सुनिश्चित करना; (ii) शैक्षिक संस्थाओं और प्रयोगशालाओं में भारतीय रेलवे से सम्बन्धित स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा उनकी पहल करना और उनमें समन्वय एवं समायोजन करना; (iii) सड़क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना; लगभग एक दर्जन परियोजनाएं शुरु की गईं- सेटेलाइट पर आधारित रेल नेविगेशन (आज करीब सत्तर रेलों में कार्यान्वित - नई दिल्ली से छूटने वाली राजधानियों और शताब्दियों सहित); व्हील इम्पेक्ट लोड डिटेक्शन सिस्टम; इम्प्रूवड व्हील मेटाल्लुरगी (व्हीलस एण्ड एक्सेल्स फैक्ट्री दुर्गापुर द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई-व्हील लाइफ में १३ प्रतिषत से ज्यादा सुधार की रिपोर्ट); एण्टी-कॉरोसिव रेल्स ('सेल' द्वारा क्रियान्वित केमेस्ट्री); ग्रीन टायलॅट्स (चेन्नई में परीक्षणाधीन); और डिरेलमेंट प्रीवेन्शन मैकेनिजम।

सड़क सुरक्षा की भारत द्वारा उपेक्षा और ज्यादा चौंकने वाली है। देश में प्रति वर्ष लगभग ८०,००० लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। अच्छी सड़कें बनाने के अलावा भारत में सड़क सुरक्षा के रिकार्ड को सुधारने हेतु अधिक मजबूत विधिक, प्रषासनिक और प्रौद्योगिकीय पहलों की जरुरत है। सड़क सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा मिषन परियोजना से कुछ चीजें ली जा सकती है जैसे जीपीएस आधारित क्षेत्रों में वाहन पर नजर और सड़कों की मॉनिटरिंग, नियंत्रण और सिग्नल प्रणालियां, छोटी कारों तथा ट्रकों व बसों पर इलेक्ट्रोनिक स्थायित्व नियंत्रण इत्यादि। भारतीय जनता पार्टी सड़क सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी मिशन (Technology Mission for Road Safety) शुरु करने हेतु प्रतिबद्ध है।

ई–सिक्योरिटी

- बाह्य प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना
- निम्नलिखित के लिए डिजिटल सिक्योरिटी ब्यूरो, स्वतंत्र एजेंसी उत्तरदायी होगी
  - साइबर युद्ध (वॉरफेयर)
  - साइबर पर आतंकवाद के हमले से मुकाबला
  - राष्ट्रीय डिजिटल परिसम्पतियों की साइबर सुरक्षा

ई-सिक्योरिटी

भारतीय जनता पार्टी जिन अनेक मुद्दों को लगातार मुखरित करती रही है उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर रहा है। हम मानते हैं कि भारत को आतंक-विरोधी पोटा जैसे कठोर कानूनों की जरुरत तो है ही, साथ ही एक सुगठित समन्वित उच्च स्तरीय गुप्तचर तंत्र, एक सक्रिय कानून लागू करने वाली फोर्स और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अपराध करने वालों से निपटने के लिए एक डिजिटल सिक्योरिटी तंत्र की भी आवश्यकता है। हम इस तथ्य से अभिप्रेरित हैं कि ९/११ के आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका द्वारा उठाए गए सुरक्षा कदमों के बाद वहां अभी तक कोई आतंकीवादी घटना नहीं घटी है।

आधुनिक संचार नेटवर्क : विभिन्न प्रदेशों के पुलिस बलों को जोड़ने वाले संचार आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता काफी खस्ता है। 'पोलनेट' (POLNET) सेटेलाइट पर आधारित संचार नेटवर्क जो विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों को जोड़ता है, का क्षेत्र सीमित है। भारतीय जनता पार्टी की योजना आईपी पर आधारित, एक राष्ट्रव्यापी वाइड-हाई-बैंडविड्थ जीपीएस आधारित, डिजिटल ट्रंकड रेडियो सिस्टम, ऑप्टिक फाइबर और सेटेलाइट्स को आधार बनाकर लागू करने की है। यह प्रत्येक पुलिसवाले को राष्ट्रीय डाटा मॉनिटरिंग सेंटर से जोड़ेगा। यह एक मिश्रित प्रणाली होगी जिसमें वायॅस, वीडियो और डाटा-प्रसारण और वन-टू-वन मोड समाहित होगा। देश में प्रत्येक पुलिस वाला एक मानक हैंडहेल्ड सिस्टम लेकर चलेगा जो कम्युनिकेटर होने के साथ-साथ कम्प्यूटर भी होगा।

समग्र सूचना प्रणाली : जब तक एक पुलिस संचार नेटवर्क मजबूत अपराध सूचना प्रणाली से जुड़ा नहीं होगा तब तक उसकी ज्यादा प्रभावोत्पकता नहीं होगी। भाजपा की योजना राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) को उन्नत करने और साथ ही इसकी भूमिका को राष्ट्रीय अपराध डाटाबेस मैनेजर के रुप में एक मानक संस्था बनाने की है जो प्रदेश स्तरीय ब्यूरोक्स के समान ही होगा। एनसीआरबी और इससे जुड़ी संस्थाएं अपराध संबधी डाटा एक राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो और इससे जुड़ी शाखाएं अपराधिक तथ्यों को एक न्यूटरल स्टैंडर्ड फार्मेट यंत्र (वैष्विक न्याय एक्सएमएल डेटा स्टोरेज मॉडल के समकक्ष) में अपराध से संबंधित डाटा डालकर स्टोर करेंगे ताकि कोई भी सूचना किसी भी समय पुलिसकर्मी द्वारा कम्प्यूटर के जरिए प्राप्त की जा सके। वर्तमान में लगभग १० से १५ प्रतिशत पुलिस स्टेशन ही देश में आवश्यक आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए हैं और केवल जिला स्तर पर ही सक्षम पुलिस वालों द्वारा राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर सूचना संकलित की जाती है। यहां उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार (१९९८-२००४) ने पहली बार केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रुप से दी गई राशि से पुलिस बल की मदद के लिए पुलिस आधुनिकरण निधि की स्थापना की थी। यह श्री लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा उठाये गए कई नए कदमों में एक कदम था।

बाह्य सुरक्षा: ऐसे युग में जब साइबर स्पेस में घुसपैठ हमारी संरचनाओं को ध्वस्त करने अथवा क्षति पहुचाने के उद्देश्य से की जा रही है और आतंकवादियों की संचार- व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, उसमें साइबर स्पेस का इस्तेमाल विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है जिससे हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। भारत के साथ विरोधी संबंध रखने वाले देश एक ऐसे सिद्धांत पर काम कर रहे हैं जिसका लक्ष्य हमारे संप्रेषण और सूचना नेटवर्क को ध्वस्त करना है ताकि युद्ध के समय हमारे सूचना तंत्र को पंगु बनाया जा सके। दुर्भाग्यवश, यूपीए सरकार की ओर से इसे नजर अदांज किया गया जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

भाजपा रक्षात्मक एंव आक्रमक क्षमता विकसित करने के साथ ऐसी नीति में विश्वास करती है जो हमारे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए जरुरी है इन कार्यों के लिए नेशनल टेक्निकल फैंसीलिटीस आर्गेनाइजेशन (NTFO) एनडीए की सरकार द्वारा गठित किया गया था जिसकी यूपीए द्वारा उपेक्षा की गई है। इसे उन्नत बनाने की जरुरत है ताकि हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकें। इससे न सिर्फ हमारे साइबर स्पेस में विरोधियों को प्रत्युत्तर देने में हमारे देश को मदद मिलेगी बल्कि यह खुफिया सूचना को इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने में एक प्रभावी मंच सिद्ध होगा। देष को एक सम्मन्वित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना की जरुरत है जिसमें बाह्य एवं आतंरिक सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। हमारे देश को एक स्वतंत्र डिजिटल सुरक्षा एजेंसी की भी जरुरत है जिसके उपर साइबर युद्ध, साइबर पर आतंकवाद के मुकाबले को रोकने और राष्ट्रीय डिजिटल परिसंपत्तियों की साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी।

डोमेस्टिक हॉस्टिंग इंडस्ट्री

- डोमेस्टिक हॉस्टिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन
- आज ६० प्रतिशत सर्वर विदेश से 'होस्ट' किए जाते हैं
- इन सर्वर्स को भारत में स्थानांततरित करके हम ५० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ प्रभार बचा सकेंगे
- विशेष इंटरनेट जोन (एसआईजेड) : बिजली की गारंटीशुदा उपलब्धता; सुस्पष्ट सुरक्षा

सॉफ्टवेयर और बीपीओ के बाद हॉस्टिंग उद्योग अगला फोकस होगा।

घरेलू हार्डवेयर उद्योग

- भारत की ३६ बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आवश्यकताओं में से ५० प्रतिशत से भी कम का स्थानीय तौर पर उत्पादन किया जाता है।
- भारत के पास १.५ ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल हार्डवेयर इंडस्ट्री का केवल २.५ प्रतिशत ही उपलब्ध है।
- भारत द्वारा घरेलू हार्डवेयर उद्योग को प्रोत्साहन देने से सन् २०१२ तक ग्लोबल मार्केट का ५ प्रतिशत हासिल किया जा सकता है।

हार्डवेयर और हॉस्टिंग इन्डस्ट्रीज

भाजपा कम्प्यूटिंग की कीमत और कम्प्यूटर हार्डवेयर और इंटरनेट हॉस्टिंग की कीमतों को कम करने के प्रति सचेत हैं। भारत पहले ही साफ्टवेयर और बीपीओ उद्योगों में अग्रणी हो चुका है। हमारी योजना है कि भारत हॉर्डवेयर और हॉस्टिंग में नेतृत्व अपने हाथ में ले।

घरेलू हार्डवेयर उद्योगः वर्ष २००७-२००८ में भारत की इलेक्ट्रानिक (आईटी और औद्योगिक उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स) हार्डवेयर मांग ३६ बिलियन डालर थी। यद्यपि केवल ५० प्रतिशत का ही घरेलू तौर पर उत्पादन हुआ, शेष आयात किया गया। और जो घरेलू तौर पर उत्पादित किया गया वह दुनिया के हार्डवेयर उत्पादन उद्योग के १.५ बिलियन डालर का २.५ प्रतिशत था।

आई.टी. हार्डवेयर (समूचे इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर का एक हिस्से) की बात करें तो घरेलू १० बिलियन डालर की आईटी हार्डवेयर की जरुरत का ७० प्रतिशत आयात किया जाता है।

भाजपा देश में संतुलित और समग्र आईटी उद्योग बनाने के उद्देश्य से विशाल इलेक्ट्रानिक्स और आई.टी. हार्डवेयर उद्योग विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। घरेलू उत्पादन और उपयोग के लिए हम कम अप्रत्यक्ष कराधान के आधार पर आईटी हार्डवेयर पार्क स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा, उत्पादनकर्ताओं को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे। दीर्घकालीन निवेशों को सुगम बनाने के लिए कराधान प्रणाली में स्पष्टता और निश्चितता रहेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि भारत का घरेलू हार्डवेयर उद्योग सन् २०१२ तक विश्व बाजार का ५ प्रतिशत हिस्सा उत्पादित करने लगे।

घरेलू हॉस्टिंग उद्योगः ६० प्रतिशत से ज्यादा सर्वर जो भारतीय वेबसाइटों को हॉस्ट करते हैं, भारत से बाहर स्थित है। हमसे न केवल भारतीय बेवसाइटों और भारतीय उद्योगों को विदेशी सरकारों के नियमों और कानूनों पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। लेकिन साथ ही हॉस्टिंग की कीमत भी बढ़ती है जिससे यह ज्यादा मंहगी अतंर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ के उंचे उपयोग की ओर ले जाती है।

एक सुदृढ़ नीति जो हॉस्टिंग उद्योग को भारत में लाने को प्रोत्साहित करती है तो इससे अतंर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ शुल्क का ५० प्रतिशत से ज्यादा बचाने में सहायता मिलेगी-इससे सम्बंधित अनेक उद्योगों को भारत में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इसलिए हम उच्च बैंडविड्थ से राष्ट्रीय इंटरनेट आधार को जोड़ने वाले विशेष इंटरनेट जोन्स् का प्रस्ताव करते हैं। विशेष इंटरनेट जोन्स् को बिजली की गारंटीशुदा उपलब्धि, पूर्ण सुरक्षा और विशेष इंटरनेट जोन्स् के बीच आपदा निवारण ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा जो विभिन्न भूकम्पी क्षेत्रों में होंगे।

हॉस्टिंग उद्योग की सर्वाधिक संचालन लागत बिजली होती है जो ईंधन शक्ति वाले सर्वरों के लिए आवश्यक है तो उनसे पैदा होने वाली विशाल गर्मी को ठंडा करने के लिए भी जरुरी है। इसलिए विशेष इंटरनेट जोन्स् उत्तर के पहाड़ी प्रदेशों और पूर्वोत्तर भारत के प्रदेशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे जहां की ठंडी जलवायु बिजली की खपत घटाएगी।

घरेलू हार्डवेयर उद्योग

- भारत की ३६ बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आवश्यकताओं में से ५० प्रतिशत से भी कम का स्थानीय तौर पर उत्पादन किया जाता है।
- भारत के पास १.५ ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल हार्डवेयर इंडस्ट्री का केवल २.५ प्रतिशत ही उपलब्ध है।
- भारत द्वारा घरेलू हार्डवेयर उद्योग को प्रोत्साहन देने से सन् २०१२ तक ग्लोबल मार्केट का ५ प्रतिशत हासिल किया जा सकता है।

डिजिटल संप्रभुता

- डिजिटल संप्रभुता के बारे में चिन्ता
- सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी साफ्टवेयर 'खुले मानकों' पर आधारित
- आई.टी. मानक निर्धारण की भूमिका बीआईएस से अलग एक नए निकाय में तैयार की जाएगी

डिजीटल क्रांति

डिजिटल संप्रभुता

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते भारत के हितों को सर्वप्रथम आगे रखती है। फिर चाहे वह आर्थिक संप्रभुता हो या परमाणु संप्रभुता, भाजपा हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में किसी से पीछे नहीं है। इसलिए जब भाजपा डिजिटल युग को देखती है और जांचती है कि देश किस हद तक अपनी डिजिटल संप्रभुता को अक्षुण्ण रख पाया है तो पार्टी पाती है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करने में अधिक सक्रिय नहीं रह पाए हैं। इसके दो उदाहरण हैं :

- यूआरएल नामकरण (जैसेः www.example.com) प्रक्रिया अमेरिका स्थित कम्पनी आईसीएएनएन (ICANN) द्वारा नियंत्रित होती है जो पूरी तरह अमेरिकी अधिकार-क्षेत्र में है। भारत में किसी भी 'डोमेन' नाम के लिए हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से आईसीएएनएन को भुगतान करना पड़ता है। यह इतनी बड़ी समस्या नहीं है परन्तु तथ्य यह है कि यूआरएल नामकरण नीतियां बनाने पर हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए बगैर प्रतिनिधित्व के टैक्स क्यों?

- दूसरा मुद्दा डिजिटल मानकों के पूरे व्यवसाय से जुड़ा है। पश्चिमी कम्पनियां/व्यक्ति विविध हल्की प्रौद्योगिकों को पेटेंट कराते हैं और वहां से आईएसओ (ISO) और आईईईई (IEEE) जैसे अतंर्राष्ट्रीय मानक संगठनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरा विश्व इन मानकों का पालन करे। और दुनिया इन 'मानको' का उपयोग करते हुए इन पश्चिमी कम्पनियों को जिनका इन प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण (IPR) है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से रॉयल्टी देती हैं। यदि हम भौतिक मानकों जैसे मीटर, ग्राम, लीटर इत्यादि का उपयोग करने पर कोई शुल्क नहीं देते हैं तो डिजिटल मानकों पर रॉयल्टी देने की क्या तुक है?

भाजपा इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय अभिमत बनाने का प्रस्ताव करती है कि इंटरनेट का रखरखाव और नियंत्रण किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय को सौंपा जाए या आईसीएएनएन को संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्राधिकार में लाया जाए। और एक अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत को इसकी गवर्निंग बॉडी में सीट दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक नये भारतीय डिजिटल मानक स्थापित करने वाले निकाय के सृजन का प्रस्ताव करती है जो विश्व का रॉयल्टी-मुक्त, खुले, मानकों के निर्माण में नेतृत्व करे जिससे न केवल भारत अपितु पूरी दुनिया में कम्प्यूटिंग की कीमत घटेगी।

डा० स्वामीनाथन का सूचना गांव (Information Village) : इंटरनेट और सेटेलाइट, गरीबों की सेवा में

सुविख्यात कृषि विशेषज्ञ डा० एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा स्थापित रिसर्च फाउण्डेशन ने पाण्डिचेरी में एक सूचना गांव (Information Village) परियोजना स्थापित की है। गरीबों को आई.टी. के लाभ पहुंचाने और प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह परियोजना आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए पाण्डिचेरी के निकट दस गांवों को जोड़ती है। इसके तहत निरक्षरों और कम पढ़े-लिखे उपभोक्ताओं के लिए स्थानीय भाषा (तमिल) में साफ्टवेयर तथा अन्य दृश्य-श्रव्य विकसित किए गए हैं। १०० से अधिक डाटाबेस बनाए गए हैं जो नियमित तौर पर अद्यतन किए जाते हैं तथा गांव वालों को कृषि लागत की कीमतों (बीज, उवर्रक और कीटनाशकों); और लाभ (चावल और सब्जियों); विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के तहत नागरिकों को सुविधाओं; स्वास्थ्य देखभाल (डाक्टरों और समीप के अस्पतालों के पैरामेडिक्स की सूची और विशेष रुप से महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य संबधी सूचना); पशुओं की बीमारी; यातायात (रास्तों की दशा और बसों के रद्द होने वाले चक्करों); और मौसम (बुआई के उपयुक्त समय, मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों; और समुद्र में लहरों की उंचाई)- के बारे में निःशुल्क ताजा जानकारी देते हैं।

प्रत्येक केन्द्र तीन कम्प्यूटरों, टेलीफोनों, एक प्रिंटर, एक वायरलैस यंत्र और एक सोलर पैनल से सुसज्जित है। कम से कम आठ वर्षों की स्कूली शिक्षा वाले ग्राम वालंटियरों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में कम्प्यूटर चलाना, डाटा और वॉयस नेटवर्क का इस्तेमाल करना, अनपढ़ उपभोक्ताओं द्वारा की गई पूछताछ का जवाब देना और प्रबंधन की बुनियादी बातों की जानकारी देना शामिल है। यह परियोजना दलित आबादी के सदस्यों के लिए निश्चित तौर पर उपलब्ध है। परियोजना यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रशिक्षित वालंटियरों में कम से कम आधी महिलाए हों। इसके परिणामस्वरुप, लगभग आधी उपभोक्ता महिलाएं हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों ने इंटरएक्टिव सीडीज का ब्राउसिंग करने, पावर पांइट पर सलाइडस की डिजाइनिंग करने और इंटरनेट से परीक्षा के परिणाम डाउनलोड करने हेतु केन्द्रों का इस्तेमाल किया है। चूंकि मछुआरे स्थानीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए समुन्द्र में मछलियों के समूहों की जानकारी राष्ट्रीय रिमोट सेंटिग एजेंसी द्वारा सूचना गांव परियोजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। यह उपयुक्त उदाहरण है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जनता को किस तरह लाभ पहुंच सकता है

विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

"सरकार द्वारा दिए जाने वाले हरेक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लक्षित लाभार्थी तक पहुंच पाते हैं"

–1985 में उड़ीसा के सूखा प्रभावित कालाहांडी जिले के दौरे के समय एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की टिप्पणी

कांग्रेस की स्मॉल Pipeline (बीच में ही निधियों की हेराफेरी) की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की आई.टी. पाइपलाइन से निधियों के आवंटन में पारदर्शिता आयेगी और भ्रष्टाचार के लिए सजा की व्यवस्था होगी।

भारतीय जनता पार्टी के आई.टी. दृष्टिकोण से भारत को इनमें मदद मिलेगी :

1. वर्तमान आर्थिक संकट पर काबू पाना;
2. बड़े पैमाने पर उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करना;
3. भ्रष्टाचार को रोकना; और
4. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाना।
5. ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर आजीविका के लिए आने वाले लोगों की संख्या को कम करना।

भारतीय जनता पार्टी

11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

website: www.bjp.org

मुद्रक : एक्सेलप्रिंट, सी-३६, एफ एफ काम्पलेक्स झण्डेवालान, नई दिल्ली -११००५५

www.lkadvani.in